UPSC-CSE 2027/28

DAILY CURRENT AFFAIRS

ONE STOP SOLUTION

By **Faiyaz Sir**



The Indian EXPRESS

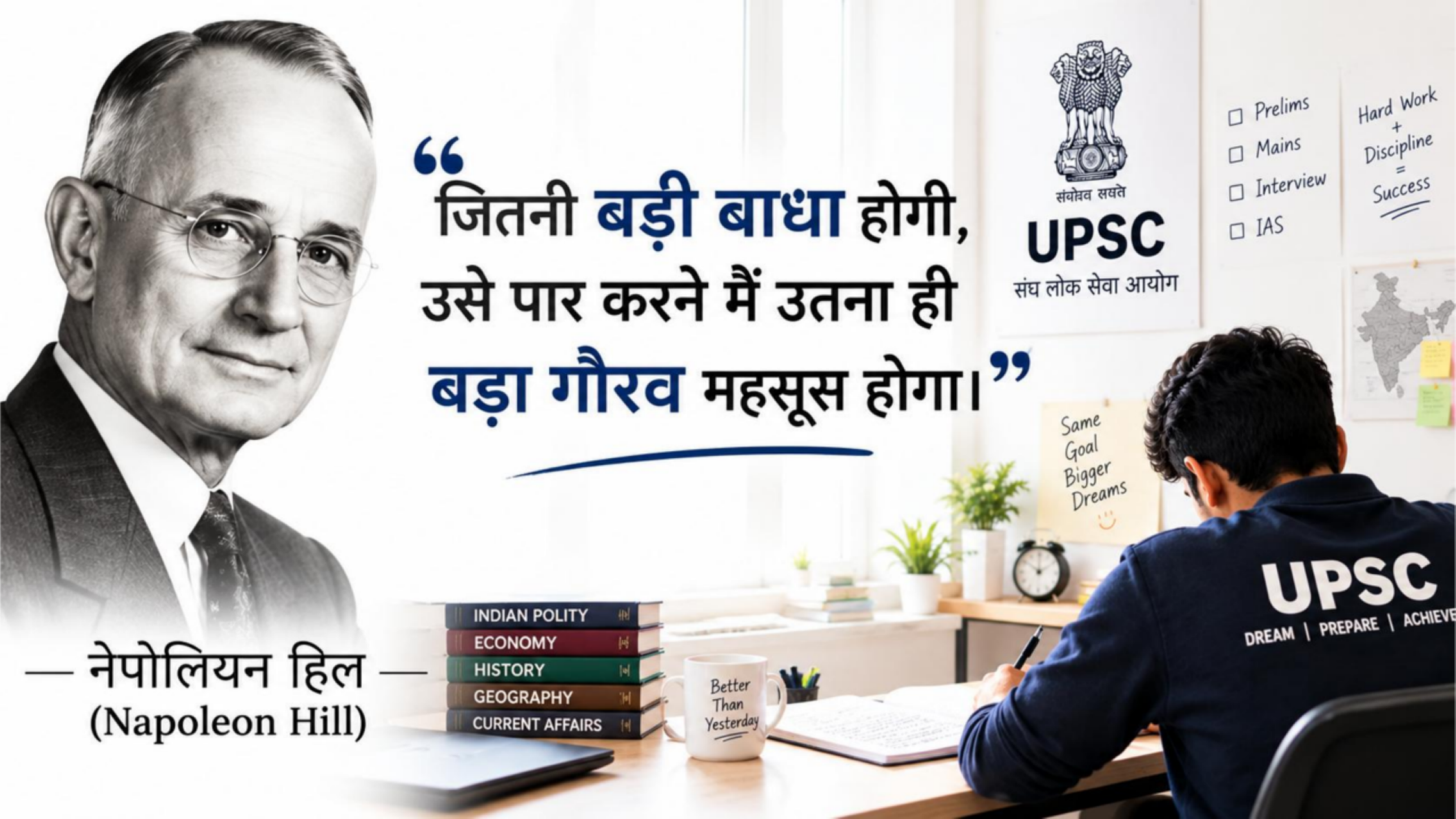
THE HINDU

pib PRESS INFORMATION BUREAU पत्र सूचना कार्यालय

26 OCTOBER

COMPLETE COVERAGE | EXAM FOCUSED | ANALYSIS MADE EASY | STATIC + CURRENT INTEGRATION

STAY AHEAD STAY PREPARED


“जितनी बड़ी बाधा होगी,
उसे पार करने मैं उतना ही
बड़ा गौरव महसूस होगा।”
— नेपोलियन हिल —
(Napoleon Hill)
संघे शक्ति कलियुगे
UPSC
संघ लोक सेवा आयोग
Prelims
Mains
Interview
IAS
Hard Work + Discipline = Success
Same Goal Bigger Dreams
INDIAN POLITY
ECONOMY
HISTORY
GEOGRAPHY
CURRENT AFFAIRS
Better Than Yesterday
UPSC
DREAM | PREPARE | ACHIEVE

आज क्या पढ़ेंगे?

- Ramsar Sites
- VB-G RAM G
- Operation Trident
- Cyclone Arnab
- Manipur Issue
- UPSC/PSC – Removal of Chairman & Members
- Tummidihatte Barrage
- Semiconductor Summit
- Form -7
- Man Ki Baat – PM
- DPDP ACT
- Molecular Machines
- US Immigration Rules
- USA-IRAN
- Saudi Houthis
- Oskar Klein Medal
- Jogen Chaudhary
- AI X Food Tech
- Shilp Samagam Mela
- 12th BRICS Parliamentary Confrence
- RBI Data Center
- Rashtriya Shahri Sammelan

PIB Backgrounder

भारत में रामसर स्थल

अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों का संरक्षण

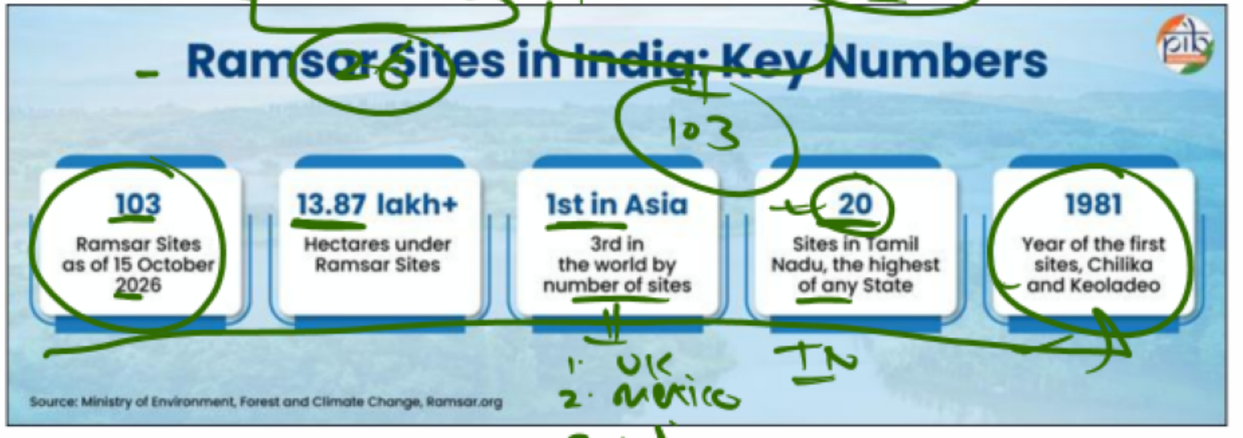
प्रविष्टि तिथि: 25 OCT 2026 9:43AM by PIB Delhi

रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के भारत के नेटवर्क का विस्तार वर्ष 2014 से अब तक लगभग चार गुना हो चुका है। नामित स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर 103 तक पहुँच गई है, जो 13.87 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। एशिया में प्रथम और विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर स्थित ये इकोसिस्टम जैव विविधता के संरक्षण, बाढ़ के प्रभाव को कम करने, भूजल पुनर्भरण तथा आजीविका को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के आधार पर भारत सरकार जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए), अमृत धरोहर, मिष्टी,और मिशन सहभागिता के माध्यम से वैज्ञानिक एवं जनभागीदारी आधारित संरक्षण को बढ़ावा दे रही है, ताकि दीर्घकालिक पारिस्थितिक सुदृढ़ता सुनिश्चित की जा सके।

Ecology & Environ.
Update - 31 Mar 2027 - Prelims

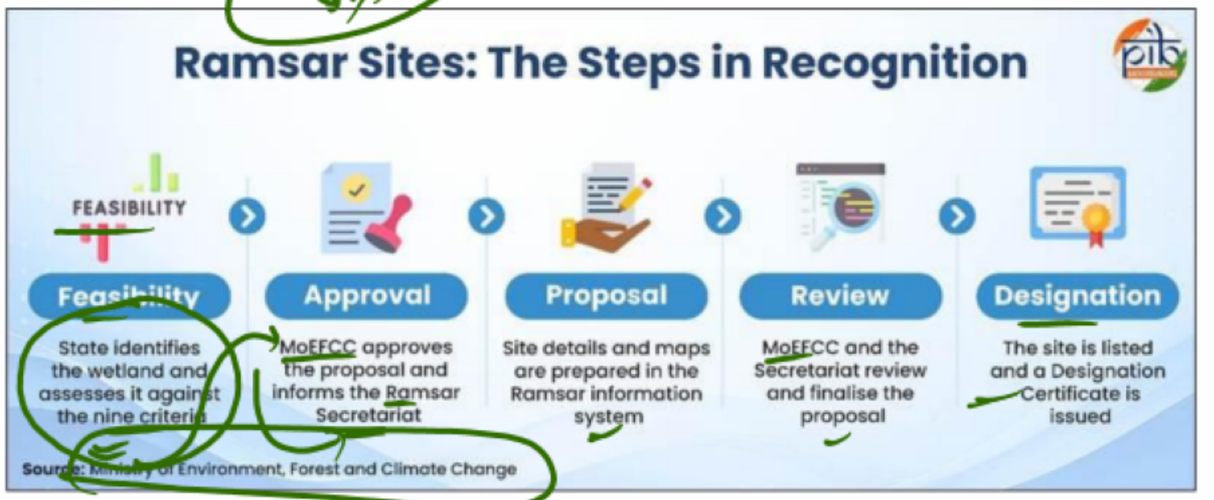
भारत में रामसर स्थल — एक नज़र

- रामसर कन्वेंशन के अनुसार, "आर्द्रभूमियाँ दलदल, दलदली भूमि, पीटभूमि या जल वाले ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम, स्थायी हों या अस्थायी, जिनमें स्थिर या प्रवाहित, मीठा, खारा या लवणीय जल पाया जाता है। इसमें समुद्री जल के वे क्षेत्र भी शामिल हैं, जहाँ निम्न ज्वार के समय जल की गहराई छह मीटर से अधिक नहीं होती।" भूमि और जल को जोड़ने वाली आर्द्रभूमियाँ मीठे जल का भंडारण करती हैं, भूजल का पुनर्भरण करती हैं, बाढ़ के प्रभाव को कम करती हैं तथा मत्स्य पालन और कृषि को बनाए रखती हैं। ये प्रवासी पक्षियों और समृद्ध जैव विविधता को भी आश्रय प्रदान करती हैं, जिससे ये पृथ्वी के सर्वाधिक उत्पादक इकोसिस्टमों में शामिल हैं।
- वैश्विक स्तर पर इन प्राकृतिक पर्यावासों का संरक्षण **आर्द्रभूमि कन्वेंशन** अथवा **रामसर कन्वेंशन** नामक अंतर-सरकारी संधि के अंतर्गत किया जाता है। इसे **2 फरवरी 1971** को ईरान के रामसर शहर में स्वीकृत किया गया था और इसे वर्ष 1975 में लागू किया गया। अक्टूबर 2026 तक, इसमें **172** संविदाकारी पक्ष शामिल हैं तथा इसके अंतर्गत विश्वभर में **2,53** से अधिक स्थल **"रामसर स्थल"** के रूप में नामित किए जा चुके हैं।
- भारत, जहाँ बड़ी संख्या में आर्द्रभूमियाँ मौजूद हैं, **1 फरवरी 1982** को इस कन्वेंशन का पक्षकार बना। तब से देश में रामसर स्थलों के नेटवर्क का निरंतर विस्तार हुआ है। वर्तमान में भारत में **103 रामसर स्थल** हैं, जो कि वर्ष 2014 में मात्र 26 स्थलों की तुलना में लगभग चार गुना वृद्धि दर्शाते हैं। स्थलों की संख्या के आधार पर भारत का नेटवर्क **एशिया में प्रथम** और **विश्व में तीसरे स्थान** पर है। कुल मिलाकर ये स्थल 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में **13.87 लाख हेक्टेयर** से अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं।



रामसर स्थलों को समझना

- रामसर स्थल ऐसी आर्द्रभूमि होती है, जिसे रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया है। इन स्थलों को उनके पारिस्थितिक, वनस्पति-विज्ञान संबंधी, प्राणी-विज्ञान संबंधी, लिम्नोलॉजिकल अथवा जलविज्ञान संबंधी महत्व के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। रामसर कन्वेंशन के तीन प्रमुख स्तंभ हैं। ये हैं—सभी आर्द्रभूमियों का विवेकपूर्ण उपयोग, रामसर स्थलों का नामांकन एवं उनका प्रभावी प्रबंधन, तथा आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।



किसी आर्द्रभूमि को कैसे नामित किया जाता है

- भारत में इस प्रक्रिया की शुरुआत राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा उपयुक्त आर्द्रभूमि की पहचान करने से होती है। इसके बाद, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नामांकन के अनुमोदन की प्रक्रिया का समन्वय करता है और प्रस्ताव को रामसर सचिवालय के पास भेजता है।

रामसर स्थल के रूप में घोषित किए जाने के मानदंड

- किसी आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए निर्धारित नौ मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना आवश्यक है। ये मानदंड दो समूहों में विभाजित हैं, जिनमें आर्द्रभूमि के प्रकार तथा जैव विविधता का संरक्षण शामिल हैं।

समूह	मानदंड	आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की माना जाना चाहिए
समूह क: आर्द्रभूमि के प्रकार		
	मानदंड 1	यदि इसमें संबंधित जैव-भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी प्राकृतिक या लगभग प्राकृतिक आर्द्रभूमि प्रकार का प्रतिनिधि, दुर्लभ या अद्वितीय उदाहरण मौजूद हो।
समूह ख : जैव विविधता		
प्रजातियों और पारिस्थितिक समुदायों पर आधारित मानदंड	**मानदंड 2**	यदि यह असुरक्षित, संकटग्रस्त या अतिसंकटग्रस्त प्रजातियों अथवा संकटापन्न पारिस्थितिक समुदायों को आश्रय प्रदान करती हो।
	मानदंड 3	यदि यह किसी विशिष्ट जैव-भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पादप और/या जंतु प्रजातियों की आबादी को आश्रय प्रदान करती हो।
	मानदंड 4	यदि यह पादप और/या जंतु प्रजातियों को उनके जीवन-चक्र के किसी महत्वपूर्ण चरण में आश्रय प्रदान करती हो अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान उन्हें शरणस्थली उपलब्ध कराती हो।
जलपक्षियों पर आधारित विशिष्ट मानदंड	**मानदंड 5**	यदि यह नियमित रूप से 20,000 या उससे अधिक जलपक्षियों को आश्रय प्रदान करती हो।
	मानदंड 6	यदि यह किसी जलपक्षी प्रजाति या उसकी उप-प्रजाति की आबादी के 1% को नियमित रूप से आश्रय प्रदान करती हो।
मछलियों पर आधारित विशिष्ट मानदंड	**मानदंड 7**	यदि यह स्थानिक मछली उप-प्रजातियों, प्रजातियों या कुलों, जीवन-चक्र के विभिन्न चरणों, प्रजातियों के बीच पारस्परिक संबंधों और/या ऐसी आबादियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को आश्रय प्रदान करती हो, जो आर्द्रभूमियों से प्राप्त होने वाले लाभों और/या उनके महत्व को दर्शाती हो तथा इस प्रकार वैश्विक जैव विविधता में योगदान देती हो।
	मानदंड 8	यदि यह मछलियों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत, प्रजनन स्थल, शिशु मछलियों के पालन-पोषण का क्षेत्र और/या प्रवास मार्ग हो, जिस पर मछलियों के भंडार (चाहे आर्द्रभूमि के भीतर हों या अन्यत्र) निर्भर करते हो।
अन्य टैक्सा या वर्गकों पर आधारित विशिष्ट मानदंड	**मानदंड 9**	यदि यह आर्द्रभूमि पर निर्भर किसी गैर-पक्षी जंतु प्रजातियों की एक प्रजाति या उसकी उप-प्रजाति की आबादी के 1% को नियमित रूप से आश्रय प्रदान करती हो।

क्या आप जानते हैं?

टैक्सॉन ऐसे जीवों का एक समूह है, जिन्हें उनकी समान विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जबकि टैक्सा इसका बहुवचन रूप है, जो ऐसे अनेक समूहों को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, गुलाब जैसे पुष्पीय पौधे पादप टैक्सॉन का हिस्सा हैं, जबकि तितलियाँ कीट टैक्सॉन के अंतर्गत आती हैं। जैव विविधता में उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी प्रमुख जैविक वर्गीकरण समूहों के उदाहरण हैं।

आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल करने के लाभ

रामसर सूची में आर्द्रभूमियों को शामिल करना और रामसर कन्वेंशन के प्रति प्रतिबद्धताओं को पूरा करना, जैव विविधता संरक्षण के वैश्विक प्रयासों की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देना है। रामसर स्थलों को न केवल किसी देश, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। रामसर स्थलों को नामित करने तथा उनका संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:

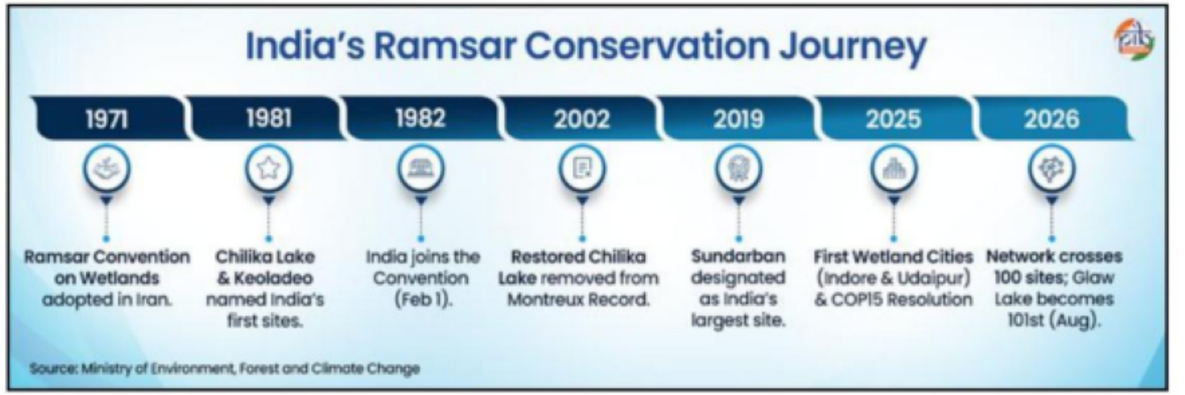
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के लिए मंच प्रदान करता है:** इससे देशों को आर्द्रभूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित प्रमुख अंतर-सरकारी मंच पर अपनी चिंताएँ और विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित रामसर पक्षकारों के 15वें सम्मेलन में भारत ने **'आर्द्रभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवनशैली को बढ़ावा देना'** विषय पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सम्मेलन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। इसे रामसर कन्वेंशन के 172 पक्षकारों, छह अंतर्राष्ट्रीय संगठन साझेदारों और अन्य पर्यवेक्षकों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ।
- **दृश्यता और पहचान बढ़ाता है:** इससे रामसर स्थलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दृश्यता और पहचान बढ़ती है, जिससे उनके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए समर्थन मजबूत हो सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानकों और मार्गदर्शन तक पहुँच प्रदान करता है:** अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की पहचान के लिए विश्व स्तर पर स्वीकृत मानकों से संबंधित नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराता है। साथ ही, आर्द्रभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग और उनके प्रबंधन की योजना बनाने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।
- **विशेषज्ञ सहायता प्राप्त करने में सहायक होता है:** इससे राष्ट्रीय और स्थल-विशिष्ट स्तर पर आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए विशेषज्ञ सलाह प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह सहायता आवश्यकता के अनुसार, रामसर सचिवालय, उसके सहयोगियों और रामसर सलाहकार मिशनों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वित्तीय सहायता को बढ़ावा देता है:** आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए सहयोग को बढ़ावा देता है। साथ ही, कन्वेंशन की लघु-अनुदान योजनाओं तथा बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों के साथ संपर्क के माध्यम से परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में भी मदद मिल सकती है।

नामांकन के बाद की प्रतिबद्धताएँ

नामांकन संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सरकार को उस आर्द्रभूमि और उसके संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। ऐसे स्थल को आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित माना जाता है। साथ ही, दिशा-निर्देशों में एकीकृत प्रबंधन योजना के साथ इन नियमों के तहत औपचारिक अधिसूचना जारी करने की भी सिफारिश की गई है।रामसर सूचना पत्रक को प्रत्येक छह वर्ष में अद्यतन करना आवश्यक है तथा स्थल की पारिस्थितिक विशेषताओं की नियमित निगरानी की जानी चाहिए। इन मानदंडों और प्रतिबद्धताओं के मार्गदर्शन के लिए भारत ने रामसर स्थलों का व्यापक और उल्लेखनीय रूप से विविधतापूर्ण नेटवर्क विकसित किया है।

1982 — 26 — 2016 — 10 — 3 — 2026

भारत के रामसर स्थल — 26 से 103 तक



भारत के रामसर स्थल ऊँचाई पर स्थित झीलों, नदी के बाढ़ मैदानों, मैंग्रोव वनों, प्रवाल भित्तियों, गाँवों के तालाबों और शहरी दलदली क्षेत्रों तक फैले हैं। **तमिलनाडु** में सर्वाधिक **20 स्थल** हैं, जबकि **उत्तर प्रदेश 14 स्थलों** के साथ दूसरे स्थान पर है। इन स्थलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, अकेले वर्ष 2025 में 11 आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया, जिससे देश में इनकी कुल संख्या 96 हो गई। उत्तर प्रदेश स्थित सुरहा ताल जून 2026 में भारत का **100वाँ स्थल**, जबकि अगस्त में ग्लॉ झील को **101वें स्थल** के रूप में शामिल किया गया। **चंडीगढ़ की सुखना आर्द्रभूमि** और **उत्तर प्रदेश की सौज झील** को सूची में नवीनतम स्थलों के रूप में शामिल किए जाने के साथ ही 15अक्टूबर 2026 तक, भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर **103** हो गई।

क्या आप जानते हैं?

भारत के प्रथम रामसर स्थल

ओडिशा की **चिल्का झील** और राजस्थान के **केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान** को 1 अक्टूबर 1981 को भारत के प्रथम रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया था। सफल पारिस्थितिक पुनर्स्थापन के बाद, चिल्का झील को वर्ष 2002 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया। बाद में, चिल्का विकास प्राधिकरण को रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है: मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर स्थलों का एक ऐसा रजिस्टर है, जिसमें उन स्थलों को शामिल किया जाता है, जहाँ पारिस्थितिक विशेषताओं में परिवर्तन हो चुका है, हो रहा है या होने की आशंका है। यह उन आर्द्रभूमियों की पहचान करता है, जिन्हें संरक्षण के लिए प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है, तथा उनकी निगरानी, सुधारात्मक उपायों और संसाधनों के आवंटन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। किसी स्थल को संबंधित देश और प्रासंगिक वैज्ञानिक विशेषज्ञों के परामर्श से इस रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। सफल सुधारात्मक उपायों का दस्तावेजीकरण हो जाने या पारिस्थितिक परिवर्तन का खतरा समाप्त हो जाने पर उस स्थल को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है।



भारत की रामसर स्थलों की सूची में हाल ही में शामिल किए गए स्थल

सखना आर्द्रभूमि (चंडीगढ़) शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में वर्ष 1958 में बनाया गया एक मानव-निर्मित जलाशय है। यह पलास फिश ईगल, कॉमन पोचार्ड और ब्लैक पोंड टर्टल जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है। मध्य एशियाई फ्लाईवे से होकर आने वाले प्रवासी पक्षी भोजन प्राप्त करने और शीतकाल बिताने के लिए इस आर्द्रभूमि पर निर्भर रहते हैं।



सौज झील (उत्तर प्रदेश) मैनपुरी जिले में स्थित बाढ़ के मैदान की एक उथली झील है, जहाँ 30,000 से अधिक जलीय पक्षी नियमित रूप से आते हैं। यह सारस और वृहद चित्तीदार चील जैसी लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों को घोंसले बनाने तथा भोजन की तलाश करने के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करती है। इसके पवित्र कमल और जंगली गन्ने के घने क्षेत्र घोंसले बनाने वाले पक्षियों, मछलियों और उभयचरों को आश्रय प्रदान करते हैं।



क्या आप जानते हैं?

सबसे बड़ा रामसर स्थल

पश्चिम बंगाल में स्थित **सुंदरबन आर्द्रभूमि** को 30 जनवरी 2019 को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। यह **4,23,000 हेक्टेयर** क्षेत्रफल के साथ भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। यहाँ भारत के कुल मैंग्रोव क्षेत्र का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पाया जाता है और विशिष्ट जलीय शिकार कौशल वाली बाघों की आबादी है।



रामसर स्थल संरक्षण में किस प्रकार सहायक होते हैं

रामसर का दर्जा प्राप्त होने से नामित आर्द्रभूमियों को वैश्विक पहचान, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही, प्रत्येक स्थल की पारिस्थितिक विशेषताओं के संरक्षण के लिए उचित योजना बनाने और नियमित निगरानी करने की स्पष्ट जिम्मेदारी भी राज्यों पर आती है।

- **इकोसिस्टमों का पुनर्स्थापन**: चिल्का झील इसका उदाहरण है कि निरंतर पुनर्स्थापन के प्रयास किस प्रकार किसी आर्द्रभूमि और उस पर निर्भर समुदायों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। वर्तमान में यह लैगून मछलियों की 118 प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है तथा जलीय पक्षियों के प्रजनन, शीतकालीन प्रवास और प्रवास के दौरान विश्राम का महत्वपूर्ण स्थल है।
- **आजीविका को बनाए रखना:** पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि लगभग 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले मछली के तालाबों के माध्यम से शहर के अपशिष्ट जल का प्राकृतिक रूप से शोधन करती है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 10,500 टन मछली का उत्पादन होता है और लगभग 50,000 लोगों को सीधे तौर पर सहायता देते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन क्षमता बढ़ाना**: सुंदरबन के मैंग्रोव वन अंतर्देशीय क्षेत्रों को तूफानों, चक्रवातों, ज्वारीय लहरों और खारे पानी के प्रवेश से बचाते हैं। ये मछलियों और घोंघो जैसे जलीय जीवों के प्रजनन एवं पोषण स्थल के रूप में भी कार्य करते हैं, जिससे भारत के संपूर्ण पूर्वी तट पर मत्स्य संसाधनों को बनाए रखने में सहायता मिलती है।
- **लुप्तप्राय प्रजातियों का पुनरुद्धार:** पंजाब के ब्यास संरक्षण रिज़र्व में भारत की लुप्तप्राय सिंधु नदी डॉल्फ़िन की एकमात्र ज्ञात आबादी है। वर्ष 2017 में शुरू किए गए पुनर्स्थापन कार्यक्रम के अंतर्गत 47 घड़ियालों को नदी में छोड़ा गया, जो लगभग तीन दशकों बाद इस नदी में उनकी वापसी का प्रतीक था। नदी का यह 185 किलोमीटर लंबा हिस्सा 500 से अधिक पक्षी प्रजातियों और 90 से अधिक मछली प्रजातियों को भी आश्रय प्रदान करता है।
- **समुदाय की सक्रिय भागीदारी:** राजस्थान की खीचन आर्द्रभूमि मात्र 54 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिवर्ष 22,000 से अधिक प्रवासी डेमोइसेल सारसों को आश्रय प्रदान करती है। समीपवर्ती गाँव के निवासी इन पक्षियों को बिजली की तारों से टकराने और आवारा कुत्तों के हमलों से बचाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते हैं।

आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए सरकारी पहलें

भारत के रामसर स्थलों के नेटवर्क को कानूनों, योजनाओं और जनभागीदारी पर आधारित एक सुदृढ़ ढाँचे का समर्थन प्राप्त है।

आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित ये नियम आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए नियामक ढाँचा प्रदान करते हैं। इनके तहत राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आर्द्रभूमि प्राधिकरणों की स्थापना की जाती है तथा अतिक्रमण, कचरा डालने और बिना उपचारित अपशिष्ट जल के निर्वहन जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

जलीय इकोसिस्टमों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए)

एनपीसीए के अंतर्गत झीलों और आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों को एक ही योजना में समाहित किया गया। वर्ष 2024 में जारी अद्यतन एनपीसीए दिशानिर्देश राज्यों को आर्द्रभूमियों के प्रबंधन के लिए एकीकृत और वैज्ञानिक ढाँचा प्रदान करते हैं।

अमृत धरोहर

अमृत धरोहर भारत के रामसर स्थलों के विशिष्ट संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देती है। इसके प्रमुख क्षेत्रों में प्रजातियों एवं आवासों का संरक्षण, प्रकृति- पर्यटन, आर्द्रभूमियों पर निर्भर आजीविका और आर्द्रभूमियों में कार्बन का आकलन शामिल हैं। इस पहल के अंतर्गत, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा क्रमशः 75 रामसर स्थलों की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की सूची तैयार करने के लिए अध्ययन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 'आर्द्रभूमियों में कार्बन भंडार के आकलन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया' जारी की गई। इसका उपयोग देशभर के 39 रामसर स्थलों में कार्बन भंडार का आकलन करने के लिए किया गया है।

मिशन सहभागिता और आर्द्रभूमि बचाओ अभियान

मिशन सहभागिता आर्द्रभूमियों के संरक्षण में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इसका 'आर्द्रभूमि बचाओ अभियान' 4 फरवरी 2023 को गोवा में शुरू किया गया था। इसके बाद से 20 लाख से अधिक नागरिक स्वयंसेवकों ने देशभर में 1.7 लाख से अधिक आर्द्रभूमियों का मानचित्रण करने में योगदान दिया है।

तटीय आवासों और ठोस आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी)

मिष्टी का लक्ष्य नौ राज्यों और चार केंद्रशासित प्रदेशों में 540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव वनों का पुनर्स्थापन करना है। अब तक, क्षरित मैंग्रोव वनों के 9,949.5 हेक्टेयर क्षेत्र के पुनर्स्थापन के लिए 88.44 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

भारत के वेटलैंड्स पोर्टल

2 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया यह पोर्टल भारत की आर्द्रभूमियों से संबंधित एक गतिशील ज्ञान भंडार के रूप में कार्य करता है। यह आर्द्रभूमि स्थलों, परियोजनाओं, पहलों और प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी तक प्रबंधकों तथा नागरिकों को एक ही स्थान पर पहुँच प्रदान करता है।

आर्द्रभूमि शहर प्रत्यायन

जनवरी 2025 में इंदौर और उदयपुर भारत के पहले ऐसे शहर बने जिन्हें रामसर के अंतर्गत आर्द्रभूमि शहर प्रत्यायन प्राप्त हुआ। इसके साथ ही वे रामसर प्रत्यायित आर्द्रभूमि शहरों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हो गए।

Prelims (प्रारंभिक परीक्षा) के प्रश्न

प्रश्न 1. भारत में रामसर स्थलों और आर्द्रभूमि (wetlands) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वर्ष 2014 से अब तक भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का नेटवर्क लगभग चार गुना हो चुका है।
2. नामित स्थलों की संख्या बढ़कर 103 तक पहुँच गई है।
3. एशिया में प्रथम और विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर स्थित ये इकोसिस्टम जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3
- D) 1, 2 और 3 सभी

Mains (मुख्य परीक्षा) के प्रश्न

- **प्रश्न 1.** "आर्द्रभूमि (Wetlands) जैव विविधता के संरक्षण, बाढ़ के प्रभाव को कम करने, भूजल पुनर्भरण तथा आजीविका को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।" इस कथन के आलोक में, भारत में रामसर स्थलों के विस्तार और वैज्ञानिक एवं जनभागीदारी आधारित संरक्षण नीतियों की विवेचना कीजिए।

पत्र सूचना कार्यालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

हमारे बारे में | प्रेस विज्ञप्ति | गैलरी | अनुसंधान इकाई | मीडिया सुविधाएं | आर्काइव | तथ्यों की जांच

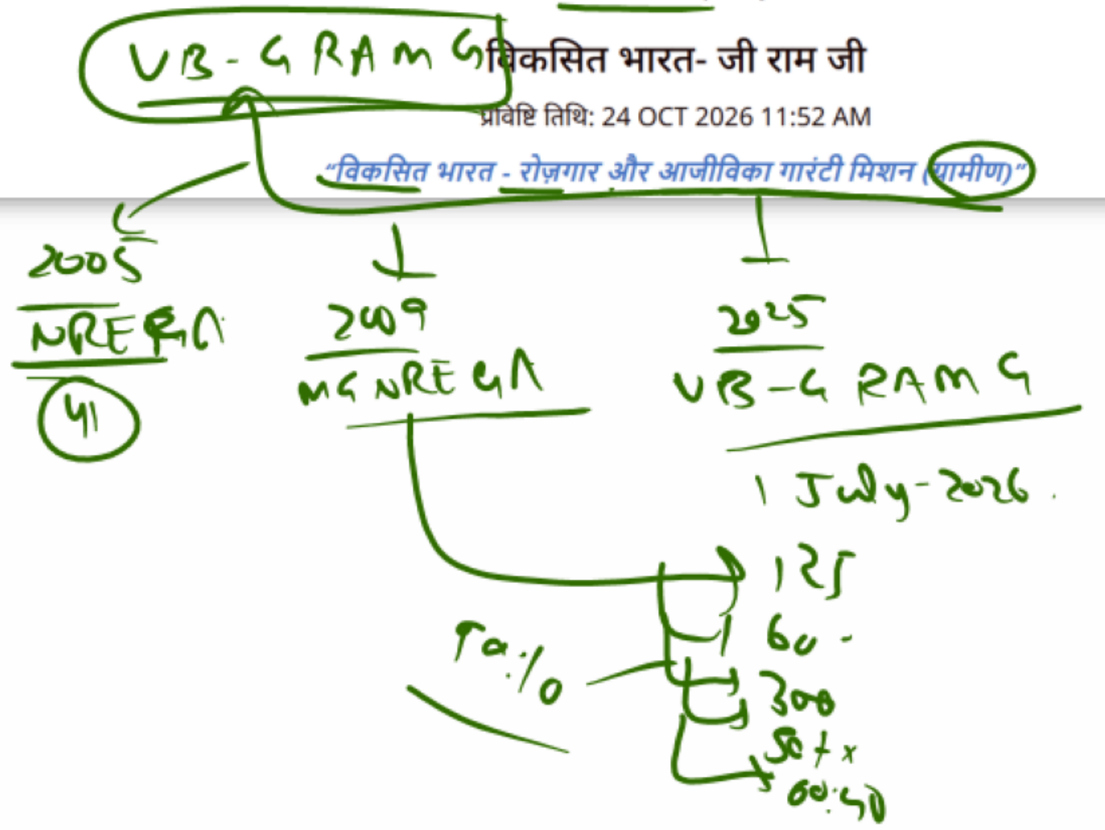
होम / All Factsheet / Factsheet Details

Rural Prosperity

विकसित भारत- जी राम जी

प्रविष्टि तिथि: 24 OCT 2026 11:52 AM

"विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)"



ग्रामीण रोज़गार और विकास के लिए नई रूपरेखा

- **'विकसित भारत @2047'** के विज़न के अनुरूप, **'विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' (VB-G RAM G)** ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अहम सुधार है। **वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025, पहली जुलाई 2026** से लागू हुआ। इसे देश के सभी ग्रामीण इलाकों में सफलतापूर्वक शुरू किया गया है। महात्मा गांधी नरेगा से वीबी-जी राम जी में परिवर्तन बिना किसी रुकावट या परेशानी के हुआ। इस नई रूपरेखा को लागू करने में सहायक डिजिटल सिस्टम इसकी शुरुआत से ही काम कर रहे थे। यह कानून हर **प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिनों के वेतन वाले रोज़गार** की कानूनी गारंटी देता है। यह गारंटी उन सभी ग्रामीण परिवारों को मिलती है जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य के लिए खुद आगे आते हैं। यह समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत के लिए **सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और परिपूर्णता** (पूरी कवरेज) को बढ़ावा देता है। यह चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है: **जल सुरक्षा, बुनियादी ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़ी अवसंरचना और खराब मौसम की घटनाओं से बचाव**।

- यह अधिनियम तालमेल और परिपूर्णता-उन्मुख नियोजन के माध्यम से **समग्र-सरकार' (Whole-of-Government)** वाले नज़रिए को संस्थागत बनाता है। इसके केंद्र में **'विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं' (वीजीपीपी)** तैयार करना है। ये ग्राम पंचायतों की अलग-अलग विकास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एकीकृत ढांचा प्रदान करती हैं।

- **'विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं' (वीजीपीपी)** वीबी-जी राम जी के अंतर्गत प्रमुख संस्थागत सुधार हैं। ये ज़मीनी स्तर पर भागीदारी वाली, सबूत-आधारित, परिपूर्णता-उन्मुख (सैचुरेशन-ओरिएंटेड) और तालमेल-आधारित नियोजन को संभव बनाती हैं।

- वीजीपीपी ग्रामीण विकास नियोजन में स्थानीय ज़रूरतों को केंद्र में रखती हैं। इन्हें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की सक्रिय भागीदारी से तैयार किया जाता है। ग्राम सभा योजनाओं के लिए ज़रूरी सिफारिश और मंज़ूरी देती है। वीजीपीपी गांवों को अपनी वास्तविक विकास ज़रूरतों, मौजूदा संपत्तियों और विकास की कमियों की पहचान करने और उसी के अनुसार कार्यों को प्राथमिकता देने में सक्षम बनाती हैं।

वीजीपीपी प्रक्रिया कैसे काम करती है

- **भागीदारी वाली प्लानिंग**: ग्राम पंचायतें ग्राम सभा की भागीदारी से स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर कार्यों की पहचान करती हैं और उन्हें प्राथमिकता देती हैं।

- **एसेट मैपिंग:** यह प्रक्रिया ग्राम पंचायत के भीतर मौजूदा संपत्तियों, अवसंरचना और सेवा वितरण में कमियों की व्यापक सूची बनाने से शुरू होती है।

- **मौजूदा संपत्तियों की कवरेज:** इस सूची में केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत बनाई गई संपत्तियां शामिल होती हैं।

- **जीआईएस-आधारित नियोजन**: योजना बनाने की प्रक्रिया में जीआईएस, **युक्तधारा, पीएम गति शक्ति** और अन्य डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है। भूस्थानिक और गैर-स्थानिक जानकारी स्थानीय ज़रूरतों और मौजूदा संपत्तियों के आधार पर प्रमाण-आधारित और एकीकृत नियोजन में सहायता करती है।

- **अंतर का आकलन (गैप असेसमेंट):** इन प्लेटफॉर्म्स से मिली जानकारी **स्थानिक नियोजन, बेहतर एसेट मैपिंग और दोहराव से बचने** में सहायता करती है। यह अवसंरचना की कमी, विकास की प्राथमिकताओं और संभावित हस्तक्षेपों की पहचान करने में भी सहायता करती है।
- **सरकार के अलग-अलग स्तरों पर तालमेल:** वीजीपीपी गांवों के एकीकृत विकास के लिए विभिन्न योजनाओं, विभागों और संबंधित पक्षों के संसाधनों और कार्यों को एक साथ लाकर **समग्र सरकार' (Whole-of-Government**) वाले नज़रिए को बढ़ावा देते हैं।
- **कई स्तरों पर एकीकरण**: वीजीपीपी को ब्लॉक, ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक साथ जोड़ा जाता है। ये समेकित योजनाएं **'विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक'** में योगदान देती हैं।**अनुमत कार्य:** वीजीपीपी ढांचा चार मुख्य क्षेत्रों में **318 प्रकार** के अनुमत कार्यों की पहचान करता है।
- वीजीपीपी प्रक्रिया का उद्देश्य रोज़गार से जुड़ी संपत्ति बनाने, बेहतर बुनियादी ढांचे और सरकारी योजनाओं के तालमेल के ज़रिए गांवों के एकीकृत विकास में सहायता करना है।

वीबी जी-राम जी: ज़मीनी स्तर पर प्रगति

- देश में **1 जुलाई 2026** को लागू होने के बाद से **24 सितंबर 2026** तक, वीबी-जी राम जी ने उल्लेखनीय प्रगति की है।
- सक्रिय कामगार: 2026-27 में **10.88 करोड़**
- बनाई गई संपत्तियां: **2.83 लाख**
- उपलब्ध कराए गए व्यक्ति-दिवस (काम के दिन): **31.69 करोड़ से अधिक**
- महिलाओं की भागीदारी: 2026-27 में **61.65 प्रतिशत**
- मांग पर कामगारों को उपलब्ध कराया गया रोज़गार: **लगभग 2.23 करोड़** ग्रामीण परिवारों से जुड़े **2.81 करोड़ से अधिक** लोगों को
- प्रगति पर कार्य : **97.17 लाख**
- भविष्य की रोज़गार मांग को पूरा करने के लिए मंज़ूर किए गए कार्य: **73.24 लाख**
- सक्रिय कार्यस्थल: **लगभग 20.16 लाख**
- देश भर में वर्तमान में काम कर रही ग्राम पंचायतों की संख्या: **लगभग 2.31 लाख**
- डीबीटी लेनदेन: 2026-27 में **3.76 करोड़**
- औसत मज़दूरी दर: **300-450 रुपये** प्रति दिन
- जारी किए गए ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्डों की कुल संख्या: **15.17 करोड़**

प्रौद्योगिकी से जुड़ी पारदर्शिता और शासन

- वीबी-जी राम जी को लागू करने में प्रौद्योगिकी मुख्य भूमिका निभाती है। डिजिटल प्रणाली कामगारों के सत्यापन, निगरानी, भुगतान और पारदर्शिता में सहायता करती हैं। वे रोज़गार को टिकाऊ संपत्ति निर्माण और ग्रामीण विकास से भी जोड़ती हैं।
- **डिजिटल सत्यापन:** e-KYC और कामगारों की उपस्थिति को फेस ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के ज़रिए दर्ज किया जाता है। इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रमाणिकता में काफी सुधार होता है।
- **कार्य की डिजिटल निगरानी**: जियो-टैगिंग, डिजिटल माप, इलेक्ट्रॉनिक मेज़रमेंट बुक्स (e-MB) और मोबाइल-आधारित निगरानी, कार्य को लागू करने के विभिन्न चरणों में निगरानी में सहायता करती हैं।
- **डिजिटल भुगतान:** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) इस ढांचे के अंतर्गत भुगतान में सहायता करता है।
- **प्रौद्योगिकी-आधारित निगरानी**: स्थानिक प्रौद्योगिकी-आधारित नियोजन, रियल-टाइम डैशबोर्ड और एआई-आधारित एनालिटिक्स सपोर्ट निगरानी, रिपोर्टिंग और सुधारात्मक कार्रवाई में सहायता करते हैं।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्षमता विकास**: समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म, नागरिकों की भागीदारी वाले प्लेटफॉर्म और बड़े पैमाने पर क्षमता विकास की पहल, कार्य को लागू करने में और सहायता करते हैं।

ज़मीनी स्तर से ग्रामीण विकास

- वीबी-जी राम जी **रोज़गार, भागीदारी वाली योजना और ग्रामीण विकास** को एक साथ लाता है। वीजीपीपी के ज़रिए, ग्राम पंचायतें स्थानीय ज़रूरतों की पहचान करती हैं, मौजूदा संसाधनों का ब्यौरा तैयार करती हैं और विकास कार्यों को प्राथमिकता देती हैं। प्रौद्योगिकी, तालमेल और डिजिटल सिस्टम कार्य को लागू करने की प्रक्रिया, पारदर्शिता और जवाबदेही को मज़बूत बनाते हैं। यह रूपरेखा रोज़गार को टिकाऊ संसाधन बनाने की प्रक्रिया से जोड़ती है, जिससे लचीली आजीविका और एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है।

Prelims (प्रारंभिक परीक्षा) के प्रश्न

प्रश्न 1. 'विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम देश के सभी ग्रामीण इलाकों में 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ है।
2. यह कानून हर प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिनों के वेतन वाले रोज़गार की कानूनी गारंटी देता है।
3. यह गारंटी उन सभी ग्रामीण परिवारों को मिलती है जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य के लिए खुद आगे आते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3
- D) 1, 2 और 3 सभी

प्रश्न 2. VB-G RAM G अधिनियम के तहत प्रमुख रूप से किन चार क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है?

- A) जल सुरक्षा, बुनियादी ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़ी अवसंरचना और खराब मौसम की घटनाओं से बचाव
- B) डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, ग्रामीण सड़क और कृषि बैंक
- C) लघु उद्योग, कौशल विकास, निपुणता और ग्रामीण पर्यटन
- D) उच्च तकनीकी कृषि, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और ग्रामीण परिवहन

Mains (मुख्य परीक्षा) के प्रश्न

- **प्रश्न 1.** "'विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' (VB-G RAM G) ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार है।" इस कथन के आलोक में इस नयी रूपरेखा की मुख्य विशेषताओं और इसके 'समग्र-सरकार' (Whole-of-Government) नज़रिए की विवेचना कीजिए।

महत्वपूर्ण तथ्य

18 held, ₹100 cr. traced in Northeast drug raids

- Central agencies, police target 'narco-hawala' network across region, the Home Ministry says
- Drive results in the freezing of 1,424 accounts, recovery of 500 detonators, cash, and assets
- Money generated flows back to Mizoram border for settlement with Myanmar suppliers, says ED

The Hindu Bureau
NEW DELHI

In a major crackdown on drug trafficking, enforcement agencies have conducted simultaneous raids at 58 locations across Assam, Mizoram, and Manipur, leading to the arrest of 18 accused persons and the detection of ₹100 crore in "hawala" transactions in connection with an international "narco-hawala" racket.

Congratulating the anti-narcotics team comprising Central agencies and police forces of the three States, Union Home Minister Amit Shah on Sunday said the Narendra Modi government had dealt another "lethal blow" to drugs with "Operation Trident".

"Our agencies launched a barrage of simultaneous crackdowns across 38 locations in Assam, Mizoram, and Manipur on October 23, smashing an international narco-cartel," Mr. Shah said in a post on X.

The operation led by the Narcotics Control Bureau in coordination with the State police and Directorate of Enforcement resulted in the freezing of 1,424 bank accounts, the attachment of assets estimated at ₹17.82 crore, the seizure of 500 detonators, and ₹12 lakh in cash, and the arrest of 18 people, a release by the Union Home Ministry said on Sunday.

The coordinated operation after days of collating confidential intelligence comprehensively covered major urban centres and sensitive border corridors such as Aizawl, Champhai, and Zokhawthar in Mizoram, Churachandpur in Manipur, and the transit corridor in the Cachar region of Assam, the Ministry said.

"The network trafficked narcotics across the borders of India, Myanmar, and Bangladesh through the Death Triangle Corridor. The offensive attests to India's Himalayan resolve to realise the mission of eradicating every drug network by December 31, 2029. India will hammer until the last nail is driven into the coffin of drug cartels," Mr. Shah said.

The multi-State operation was the result of sustained intelligence-based investigations conducted by the NCB and other agencies into the cases which uncovered a major international smuggling syndicate led by Myanmar-based kingpin Thangsintuang, alias Chintuang, alias Tluanga, the Home Ministry said. The alleged kingpin, who was arrested from Delhi in May, operated cross-border smuggling of methamphetamine and heroin into India and Bangladesh through the Myanmar-Mizoram-Manipur-Assam-Tripura corridor.

Drug control

Central agencies carried out searches over alleged trafficking of drugs from Myanmar and 'hawala' settlements of proceeds

- Local carriers were hired by Myanmar-based organisers to move consignments
- Payments routed through 'hawala' accounts receiving drug proceeds from across the Northeast
- Bank accounts in Champhai, Aizawl, and Lawngtlai of Mizoram received drug money and settled with suppliers in Myanmar, says the ED

> The offensive attests to India's Himalayan resolve to realise the mission of eradicating every drug network by Dec. 31, 2029
>
> AMIT SHAH
> Union Home Minister



Coordinated searches

In a separate press release, the Directorate of Enforcement (ED) said coordinated searches were carried out under the Prevention of Money Laundering Act, 2002, in connection with three cases alleging trafficking of heroin, brown sugar, and methamphetamine tablets from Myanmar, and "hawala" settlements of drug proceeds.

The ED's investigation has revealed that the same set of bank accounts in Champhai, Aizawl and Lawngtlai received drug money generated in Manipur, Mizoram, Assam, and Tripura, and settled it with suppliers in Myanmar.

Six arrested on money-laundering charges have been identified Kashyap G. Thakkar, Thangkhuala, T. Chatuan Vanlalgakha, Zenngaihniang, Nengzatuan Valte, and H. Gouzalal.

"Heroin and methamphetamine tablets entering Mizoram and Manipur are consumed locally and moved onward through Assam to the rest of India and Bangladesh, and the drug money generated across this chain flows back to the border towns of Mizoram for settlement with Myanmar-based suppliers. The trafficking corridor works as a two-way street through the Champhai-Zokhawthar sector of Mizoram," the ED said, explaining the *modus operandi*.

In one direction, precursor and cutting chemicals move from India to Myanmar, from where heroin, brown sugar, and meth tablets produced there are carried across the Tiau river at Zokhawthar, opposite Khawmawi, and kept at Champhai before being transported via the Champhai-Aizawl road and NH06A to Aizawl, Vairengte, and the Assam and Tripura borders.

The Myanmar-based organisers hired local carriers and moved consignments concealed in soap cases, taxis, motorcycles, and escorted truck convoys. Payments were routed through the same Champhai "hawala" accounts receiving drug proceeds from across Northeast India. Drugs are sold for cash across Manipur, Assam, Tripura, and other parts of India, with the proceeds routed to suppliers in Myanmar through "hawala" channels.

In Manipur's Churachandpur, syndicate operatives collected cash for handlers, who channelled the funds into the banking system through mini-ATM/customer service point counters.

YouTube Homework

- Nasha Mukt Bharat - २०२१
- NCB - ??
- ED -
- Operation Trident

NCB
ED
Police
PMLA-2002
NCB में नशीले पदार्थों को रोकने

महत्वपूर्ण तथ्य

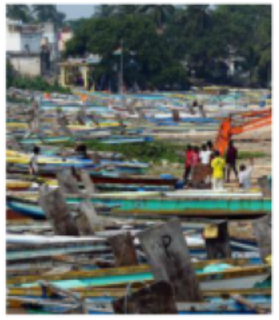
Andhra Pradesh, Odisha on alert as deep depression develops over Bay of Bengal

The Hindu Bureau
BHUBANESWAR/VIJAYAWADA

The weather system over Bay of Bengal which is expected to make landfall as a 'very severe cyclonic storm' on October 28 intensified into a deep depression on Sunday, the India Meteorological Department said.

Andhra Pradesh, where the storm is likely to make landfall, deployed several battalions of disaster management teams on Sunday and announced evacuation of people in the likely impact zones.

According to a bulletin issued by the IMD on Sunday evening, "The depression over eastcentral and adjoining Southeast Bay of Bengal moved southwestwards with speed of 5 kmph during past six hours, [and] intensified into a deep depression. It lay centered in the Bay, about 420 km north-northwest of Sri Vijaya Puram in the Andaman Islands, and 870 km east-southeast of Vishakhapatnam.



Fishing boats lie on the beach in Visakhapatnam on Sunday in view of the forecast. V RAJU

The system is likely to move nearly southwestwards, and intensify further into a cyclonic storm over eastcentral and the adjoining southeast Bay of Bengal by early morning on Monday (October 26). Then it is very likely to move west-northwestwards over the eastcentral and adjoining westcentral Bay of Bengal and intensify into a severe cyclonic storm over the westcentral Bay of Bengal on Tuesday morning (October 27), the bulletin said.

The severe cyclonic storm is then likely to move northwestwards, intensify further into a very severe cyclonic storm and reach the westcentral Bay of Bengal near the Andhra Pradesh coast on Wednesday morning (October 28), and cross the Andhra Pradesh and Yanam coasts between Bapatla and Visakhapatnam.

Response teams on alert

Andhra Pradesh State Disaster Management Authority managing director Prakhar Jain told *The Hindu* that the State has deployed 12 battalions of the State Disaster Response Force and seven battalions of the National Disaster Response Force. The State has also requisitioned three more NDRF battalions.

The Odisha government instructed eight Ministers, including two Deputy Chief Ministers, to station themselves in eight districts to supervise disaster management measures.

28 october

YouTube Homework

- Cyclone

महत्वपूर्ण तथ्य



Congress leader Alka Lamba and Saptagiri Ulaka addressing the media in New Delhi on Sunday. SHASHI SHEKHAR KASHYAP

Govt. failed to contain violence in Manipur, CM must quit: Cong.

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Alleging failure to contain renewed violence in Manipur, the Congress on Sunday demanded the resignation of Chief Minister Y. Khemchand Singh, dissolution of the State Assembly, and fresh elections, alongside an intervention by the Union government to end the violence and initiate an inclusive peace process.

No armed group or individual attacking civilians should enjoy "political protection or immunity", the party said. Congress leaders cited recent incidents of violence, including the killing of three Meitei civilians on October 19 and clashes in Kamjong district in which Kuki and Naga civilians were killed.

Addressing a press conference, party MP and Manipur in-charge Saptagiri Ulaka called for time-bound investigations and prosecution in cases of killings, firing, arson, and destruction of civilian property in the State.

The police, Mr. Ulaka alleged, used a heavy hand to suppress the protest by using tear gas shells and lathi charge against the people.

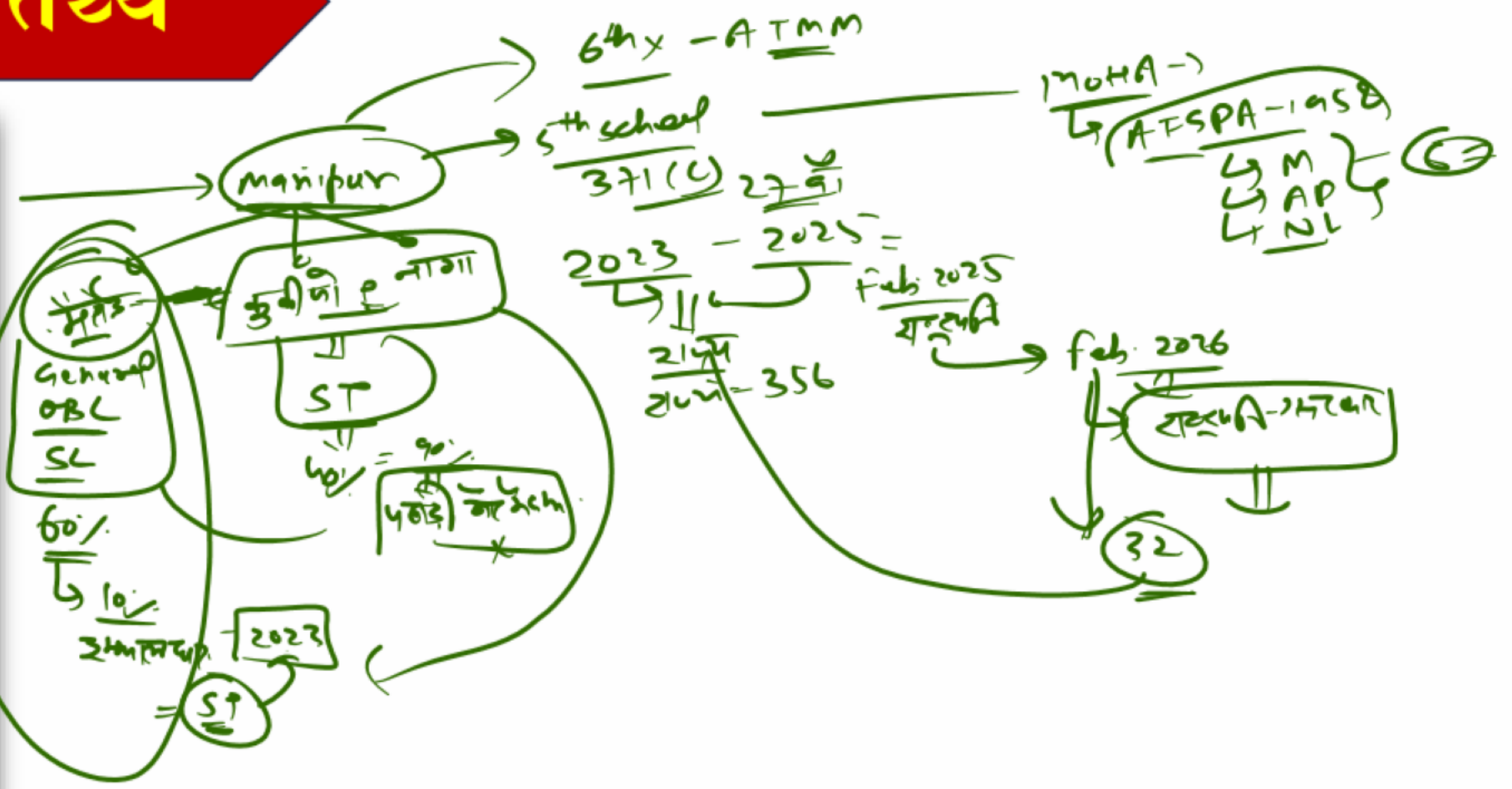
Mahila Congress president Alka Lamba, who visited Manipur earlier this month, said women affected by the conflict continued to face hardship. "The BJP government in Manipur has completely failed to stop the violence there," she said.

Sophisticated weapons

Mr. Ulaka, the Congress in-charge of Manipur, alleged that armed groups possessed more sophisticated weapons than security forces. He said around 300 people had been killed since May 2023, while nearly [illegible],000 were displaced, with about 24,000 yet to return home.

The Congress leaders called for immediate protection of civilians in vulnerable areas, strict enforcement of the suspension-of-operations ground rules, restoration of free movement across the State, and a credible roadmap for rehabilitation and the return of displaced persons.

The ethnic conflict between the Meitei and Kuki communities that began in May 2023 has claimed more than 300 lives and displaced thousands. In recent months, clashes involving Kuki and Naga groups have also been reported.



महत्वपूर्ण तथ्य

Arlekar's recommendation on KPSC chief sparks row

Former Keralam Governor sent communication to President seeking removal of Baiju over alleged irregularities; CPI(M) asks Chief Minister to clarify stand; Ministers in UDF govt. divided over move

The Hindu Bureau
THIRUVANANTHAPURAM

In an unprecedented move, former Keralam Governor Rajendra Vishwanath Arlekar has reportedly recommended to the President the removal of Kerala Public Service Commission (PSC) Chairperson M.R. Baiju over alleged irregularities in the running of the recruitment body.

The recommendation came out in the public domain hardly a few days after Mr. Arlekar left the State and has been succeeded by Om Prakash Mathur as the Governor. He is learnt to have sent the communication to President Droupadi Murmu a week before he was relieved of his duties.


Rajendra Vishwanath Arlekar

A Crime Branch investigation into the alleged irregularities in the PSC examination for certain posts in the State Planning Board is currently progressing.

The Communist Party of India (Marxist) State secretariat, which called the Governor's move unconstitutional, has demanded that the Chief Minister clarify his stand on the Governor's recommendation to the President to dissolve the PSC.

"Has the government asked the Governor to dissolve the PSC at this stage when no allegation can be proven or presented in court? It is no secret that the Sangh Parivar is targeting the PSC, after the universities in the State," said the CPI(M) in a statement.

Leader of the Opposition Pinarayi Vijayan said the recommendation to remove the Chairperson and dissolve the commission was unlawful, a violation of constitutional provisions, and gross abuse of power.

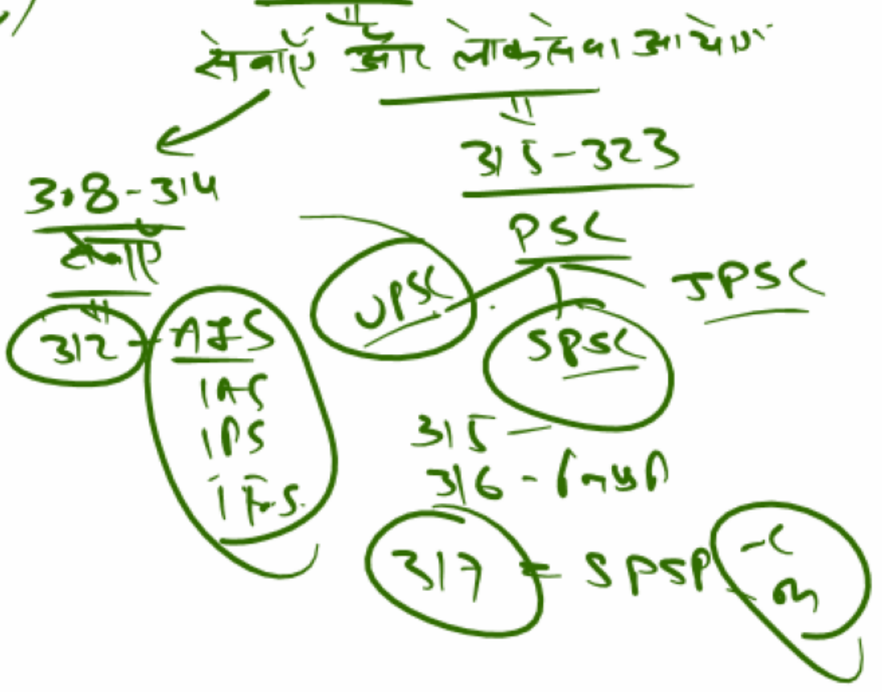
He said the move raised concerns about the use of Lok Bhavans for the BJP's political agenda. The Congress-led UDF government should clarify its stand and oppose attempts to undermine institutional autonomy, he said.

While a majority of the UDF Ministers, who spoke on Sunday, supported the Governor's move, Revenue Minister A.P. Anil Kumar called it a constitutional impropriety to hastily recommend the action without the government's knowledge when an investigation was under way.

JPSC
KPSC
KPSC

YouTube Homework

➤ **Part-14**



महत्वपूर्ण तथ्य

- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोग (State PSC) के अध्यक्ष (Chairman) और सदस्यों (Members) को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 317 (Article 317)** में स्पष्ट रूप से दी गई है।
- इन्हें पद से हटाने के आधार और प्रक्रिया निम्नलिखित हैं:

1. राष्ट्रपति द्वारा सीधे हटाया जाना (बिना जाँच के)

- राष्ट्रपति UPSC और State PSC दोनों के अध्यक्ष या सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों में बिना किसी न्यायिक जाँच के सीधे पद से हटा सकते हैं:
- **दिवालिया घोषित होना:** यदि उन्हें अदालत द्वारा दिवालिया (Insolvent) घोषित कर दिया गया हो।
- **लाभ का पद:** यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के अलावा कहीं और से वेतनभोगी नौकरी या लाभ का पद स्वीकार करते हैं।
- **मानसिक या शारीरिक अक्षमता:** यदि राष्ट्रपति की राय में वे शारीरिक या मानसिक रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करने के योग्य नहीं हैं।

2. कदाचार (Misbehaviour) के आधार पर हटाना

- यदि उन पर **कदाचार (Misbehaviour)** का आरोप लगता है, तो हटाने की प्रक्रिया इस प्रकार होती है:
- **उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की जाँच:** राष्ट्रपति इस मामले को जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेजते हैं।
- **जाँच और सिफारिश:** सुप्रीम कोर्ट मामले की जाँच करता है। यदि आरोप सही पाया जाता है, तो वह राष्ट्रपति को उन्हें हटाने की सिफारिश करता है।
- **बाध्यकारी सलाह:** सुप्रीम कोर्ट की यह सलाह **राष्ट्रपति पर बाध्यकारी (Binding)** होती है।
- **निलंबन (Suspension):** जाँच प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति UPSC के सदस्य को और संबंधित राज्य के राज्यपाल (Governor) State PSC के सदस्य को निलंबित (Suspend) कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

विवरण	UPSC (संघ लोक सेवा आयोग)	State PSC (राज्य लोक सेवा आयोग)
नियुक्ति (Appointment)	राष्ट्रपति द्वारा	राज्यपाल (Governor) द्वारा
हटाने का अधिकार (Removal Power)	**केवल राष्ट्रपति** द्वारा	**केवल राष्ट्रपति** द्वारा (राज्यपाल के पास हटाने का अधिकार नहीं है)
संविधान का अनुच्छेद	अनुच्छेद 317	अनुच्छेद 317

महत्वपूर्ण तथ्य

Revanth to meet Fadnavis for talks on Tummidihatti Barrage

The Hindu Bureau
HYDERABAD

Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy has stepped up efforts to revive the long-pending Tummidihatti Barrage across the Pranahita river at Tummidihatti on the Telangana-Maharashtra border, with the State government delegation set to hold crucial talks with Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis in Mumbai on Monday to secure consent for raising its proposed height from 148 metres to 150-152 metres Full Reservoir Level (FRL).

The Telangana delegation, led by the Chief Minister, would comprise Minister for Irrigation and Civil Supplies N. Uttam Kumar Reddy and senior officials. The Maharashtra Chief Minister would be assisted by Minister for Water Resources Radhakrishna Vikhe Patil and senior officials.



The proposed site for barrage.

In 2016, an agreement was reached between the governments, with K. Chandrashekhar Rao and Devendra Fadnavis at the helm of affairs, and the height agreed for the barrage was 148 metres. In the same meeting, the Medigadda Barrage was agreed to at 100 metres FRL. The project subsequently lost priority as the BRS government concentrated on the Kaleshwaram project.

Now, the Congress government is planning to revive the Pranahitha-Chevella project by taking up a barrage at Tummidihatti with 152 metres FRL, as originally planned in 2007, to take water by gravity and a small lift to Yellampally project. Telangana is arguing that only 2,300 acres of land would face submergence with the barrage at 152 metres FRL and less than 1,000 acres with 150 metres FRL. The State is prepared to consider 150 metres if that helps secure Maharashtra's approval.

YouTube Homework

Godavari

महत्वपूर्ण तथ्य

61,000 Form 7 applications filed by poll officials in Karnataka, none cite reason

Rishita Khanna
Pon Vasanth B.A.
BENGALURU/CHENNAI

At least 61,059 Form 7 applications seeking the deletion of names from Karnataka's electoral rolls were filed by election officials themselves, with not a single application mentioning a reason for the deletion, a mandatory requirement under the Registration of Electors Rules, 1960.

Electoral Registration Officers (EROs) and Assistant Electoral Registration Officers (AEROs), listed as the objectors in these applications, said the system "auto-generated" the forms with their digital signatures when voters could not be reached during hearings on notices issued for no mapping or logical discrepancies, and the voters were therefore marked as "ineligible".

This meant the same election machinery was raising objections to voters' names and deciding on whether they should remain on the rolls. Under the Registration of Electors Rules, 1960 an objection that is not filed in the prescribed manner, including stating the reason, is liable to be rejected.

The officials said they had been instructed to file Form 7 applications if a voter had shifted, had a duplicate entry elsewhere, was underage, had died, or was not an Indian citizen. But as the forms were auto-generated, the reason for seeking deletion was left blank. With no reason recorded, neither the voter nor anyone examining the electoral roll can establish why a particular name was marked for deletion or verify whether the removal was justified.

Moreover, these categories of voters (ASDDO or Absent, Shifted, Duplicate, Dead and Others) had already been checked during the enumeration phase of the special intensive revision (SIR), which led to more than 1.07 crore names being deleted from Karnataka's draft electoral roll. Most deletions were on the grounds of voters having permanently shifted, followed by those marked as absent.

The number of Form 7 applications filed by election officials rose sharply after the claims and objections period ended on September 23, 2026. Between August 24 and September 23, only 192 such applications were received. More than 60,800 were filed after the claims and objections period, between September 24 and October 22.

Opaque deletions

One-third of all the Form 7s generated since the beginning of Claims and Objections phase in Karnataka were filed in the name of officials, with none mentioning any reason

Total Form 7s filed since Aug 24 *(only those made available on ECI's website)*		1,81,509
Filed in the name of self		1,12,514 (62%)
Filed by the officials		61,059 (33.6%)
Filed by third parties		7,936 (4.4%)
FIVE DISTRICTS THAT SAW HIGHEST NUMBER OF FORM 7S FILED BY OFFICIALS	B.B.M.P (South)	10,374
	B.B.M.P (North)	8,443
	Bangalore Urban	8,102
	Kolar	3,392
	Chikkaballapur	3,330

The filing continued at an exceptionally high rate even as the disposal deadline approached. On October 22, the last day for disposing of claims and objections, election officials filed 10,105 Form 7 applications. Another 10,314 were filed on the previous day, October 21. On October 17 and 19, officials filed 11,132 and 11,760 applications, respectively.

Already deleted

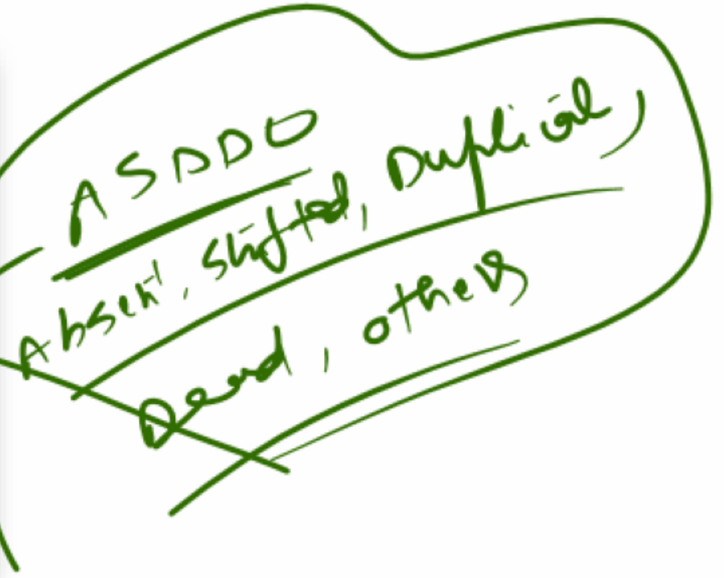
To examine the pattern, *The Hindu* obtained the EPIC numbers of several voters against whom election officials had filed Form 7 applications and cross-checked their details on the Election Commission of India (ECI) portal. In all the cases checked, the names had already been deleted from the electoral roll, including those against whom applications had been filed after September 23.

This is at odds with Rule 17 of the Registration of Electors Rules, 1960, which states that any claim or objection not lodged within the prescribed period or in the prescribed form and manner "shall be rejected by the registration officer".

It also remains unclear whether hearing notices or orders, which are mandatory before deletion, were issued in these cases, or on what grounds the names were deleted, as the relevant details had been left blank.

In the Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike South district, where election officials filed the highest number of Form 7 applications, applications filed by officials outnumbered those filed by voters or third parties. Of the 17,491 applications in the district, 10,374 were filed by officials. In the Bommanahalli Assembly constituency alone, officials filed 4,095 of the 5,757 applications received. The pattern of EROs and AEROs filing more Form-7 applications than voters or third parties was seen in at least 26 Assembly constituencies.

Karnataka's final electoral roll is scheduled to be published on December 27. Only claims and objections received by September 23 were to be considered for the final roll. Applications filed after the deadline were to be considered only for a supplementary roll after the SIR. However, *The Hindu*'s sample checks found that the names of voters cited in applications filed even after the deadline had already been deleted from the roll.



महत्वपूर्ण तथ्य

- BNSS Section 163
- Article 19 (1)
- Article 19 (3)
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- ECI
- CEC – EC's
- SIR
- RPA 1950 – 21(3)
- RPA 1950 – 28 (RER-1960 – 6,7,8)
- RPA 1951 - 29(A)
- Conduct of Election Rules 1961 – 4(A) – Form 26

महत्वपूर्ण तथ्य

Prioritise domestic products during festive season, says PM

Modi lauds initiatives in organic farming, digital healthcare, and environmental conservation in his *Mann Ki Baat* address; he cites research at the IIT-M using the Param Shakti supercomputer

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Prime Minister Narendra Modi on Sunday lauded individuals and communities for promoting organic farming, indigenous products, digital healthcare, scientific research, and environmental conservation. Their efforts were creating new opportunities and contributing to the vision of a self-reliant India, Mr. Modi said.

Ahead of the Deepavali and Chhath festivals, the Prime Minister in his *Mann Ki Baat* address urged people to prioritise domestic products under the 'Vocal for Local' campaign. He also highlighted the importance of packaging, noting that Maharashtra's 'Shabari Naturals' had received Japan's Good Design Award. A Karnataka start-up was developing packaging materials from bamboo and agricultural waste. Khadi's popularity was also growing continuously, he said.

Recalling his recent visit to Chennai, Mr. Modi highlighted the Sudha Gopalakrishnan Brain Centre at the Indian Institute of Technology-Madras, which has developed a brain imaging technology platform and will study 100 human brains. The research uses the Param Shakti supercomputer, and its data will be made available as an open source for research across fields.



Young innovators

At IIT-Madras, he also met young innovators working on gold quality testing, recovery of funds lost to bank fraud, AI-based cervical cancer screening, flying electric vehicles, fast-charging batteries for drones and electric vehicles, and AI applications in defence technology.

On healthcare, about 50 crore tele-consultations had been conducted through the e-Sanjeevani scheme, which had reached remote parts of the country, he said. Nearly 1.9 lakh 'Ayushman Arogya Mandirs' were providing healthcare facilities across the country, he added.

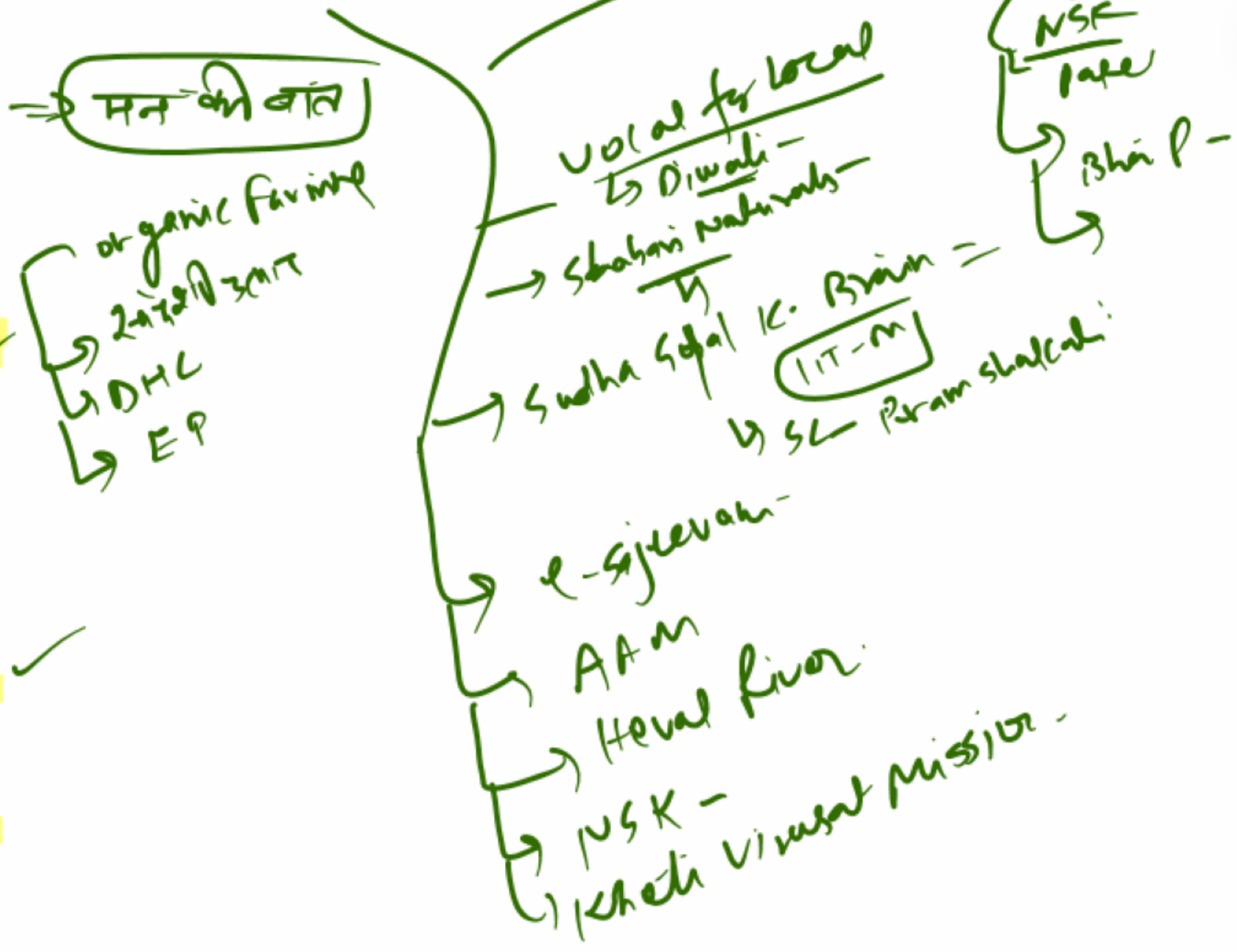
Mr. Modi paid tribute to scientist Narinder Singh Kapany, known as the 'Father of Fibre Optics', ahead of his 103rd birth anniversary on October 31. Born in Punjab's Moga district, Kapany's research on transmitting light through thin fibres helped advance modern communication networks.

Kheti Virasat Mission

The Prime Minister highlighted the efforts of the Kheti Virasat Mission in Punjab's Malwa region to promote natural cotton cultivation. Organic cotton is grown without chemicals, while naturally coloured cotton eliminates the need for additional chemicals to dye yarn and fabric. Highlighting environmental conservation, the Prime Minister referred to community efforts to revive the Heval river in Uttarakhand's Tehri Garhwal region. He also underscored the importance of organ donation, and described the decision of the family of road accident victim to donate her organs as an inspiration to society.

Mr. Modi called on people to participate in the 'Run for Unity' on October 31, marking the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, which is observed as National Unity Day.

Referring to Maharishi Valmiki's birth anniversary on October 26, he highlighted the messages of service, compassion and social harmony in the Ramayana. He also paid tribute to Bhai Parmanand, whose 150th birth anniversary falls on November 4. The British sentenced him to transportation to the Andaman Islands, popularly known as Kala Pani, Mr. Modi said, and he later entered the field of education and also taught Bhagat Singh. Bhai Parmanand was associated with the Arya Samaj and the Hindu Mahasabha for many years, he said.



महत्वपूर्ण तथ्य

India needs to train its clinical staff before erecting data shields

User data is routinely commoditised today, and passing a law assuming compliance and waiting for complaints or litigation will not suffice; as the DPDP Act comes into effect, the government must finance, build, and sustain an ecosystem that allows every health worker to comply and patients to be able to better access care

C. Aravinda

The recent conversation over the merchant discount rate on select UPI transactions raised the question of who pays for the digital convenience that millions of people enjoy. Hospitals may soon face a similar problem for strengthening their privacy even if no separate "privacy charge" appears on a patient's bill.

Protecting digital patient information will require secure systems, trained personnel, and continuous compliance. The Parliament enacted the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act 2023 in response to this need. The Act consists of 44 sections in nine chapters plus one Schedule. The government notified its Rules on November 13, 2025, with the Sections pertaining to provisions for consent managers set to kick in from November 13, 2026. The rest of the substantive obligations will start to apply from May 13, 2027.



The government should not expect every small hospital, diagnostic centre, and/or PHC to independently purchase the same privacy tools in order to enforce the DPDP Act. BERND STUDIO/UNSPLASH

THE GIST

India's DPDP Act 2023 establishes a legal framework for processing digital personal data, including health records; most obligations will take effect from May 13, 2027, while provisions relating to consent managers begin in November

The Act distinguishes between consent for medical treatment and consent for using personal health data; a patient's agreement to a procedure does not automatically permit all future uses of the resulting data

The law designates patients as data principals and hospitals as data fiduciaries, requiring secure processing, grievance redressal, and data correction or erasure mechanisms while ensuring healthcare delivery is not hindered by excessive access restrictions

Unusually difficult places

The Act is a general framework to protect digital personal data across sectors, including healthcare. In healthcare, the Act recognises that clinical consent and data consent are different. For example, persons agreeing to undergo a medical scan does not automatically mean they have agreed to every later use of the same scan, no matter how useful the hospital or doctors deem the scan data to be. While facilitating this distinction, the Act also makes room for data-processing during emergencies and specific medico-legal and public health situations.

Under the DPDP Act, the patient is the data principal (or owner) and the hospital – which usually decides why and how some information will be used – is the data fiduciary. Some external software, cloud, and/or data-processing company will serve as the data processor.

That said, hospitals are unusually difficult places in which to ensure compliance with a general data-protection law.

Unlike banks or regional transport offices, hospitals continuously create information of an intimate nature. For example, healthcare workers record a patient's clinical notes, nursing observations, diagnostics and laboratory results, ventilator readings, and prescriptions – all within hours.

At the same time, several professionals will need to access different parts of that record at different times. If access is too tightly controlled, patient care may suffer; on the other hand, unrestricted access can result in significant breaches of privacy. So the Act needs to facilitate the lawful processing of consent with reasonable security safeguards, grievance handling processes, and of course the correction or erasure of data where permissible.

Failure to take reasonable safeguards can attract a penalty of up to ₹250 crore.

Compliance costs

In the same vein, compliance requires hospital information systems with role-based access, facility to encrypt or mask data as necessary, systems to generate and preserve audit logs, backups, vendor contracts, breach response protocols, staff training, and a clearly identified person who is responsible for data governance.

Entities designated data fiduciaries must also appoint a statutory data protection officer, and smaller hospitals will need a privacy or data management lead in practice.

Further, information rarely stays within the hospital, since a cashless claim can send diagnoses and reports to an insurer or a third party administrator. Laboratories, radiology platforms, cloud vendors, and telemedicine services will create additional routes for the same record.

Even low-cost WhatsApp-based workflows that became popular because they were convenient will have to be examined for compliance and security.

Healthcare may therefore need specific DPDP provisions, either explicitly or eventually as a separate Act, to cover sector-specific uniqueness, such as small hospitals and large hospitals separately, as clinical care is more than a commercial transaction.

No uniform training

U.S. estimates show the cost of complying with the famed Health Insurance Portability and Accountability Act, or HIPAA, to be around $5 per patient a year in 2008. Estimates for 2025 suggest the cost of $498 per affected record.

In a 2023 study, researchers from India and Norway estimated that adding an integrated information and communications system to an urban primary health centre (PHC) would expand the centre's annual economic budget by 17.7%. But when the researchers applied the same model across 400 PHCs, the incremental cost fell to about 6% per PHC. The reason: common development and infrastructure costs were shared.

The finding offers an important policy clue: the government should not expect every small hospital, diagnostic centre, and/or PHC to independently purchase the same privacy tools, legal templates, and so on.

That said, the harder problem is that India has legislated faster than it has trained the people who must make the law work. Medical education teaches confidentiality and ethics, but there is no uniform DPDP-oriented National Medical Commission curriculum or standard course materials that span medicine, nursing, allied health, hospital administration, and healthcare IT training. The vendor side faces the same problem: behind every software workflow is a human being who configures access, checks claims, handles support or views data. And an untrained person handling data in a hospital can pave the way for a major breach due so little as to one leaked password. So data literacy has to become a core healthcare competency.

Building an ecosystem

The National Health Accounts 2022-23 released this year estimated the out-of-pocket expenses on healthcare to be 43.4% of total health expenditure. There is a nontrivial chance that the new costs of complying with the DPDP Act will be passed on to patients as well.

Ahead of the November 13 date, the Indian government should step in by enabling a shared infrastructure through the Unified Health Interface of the Ayushman Bharat Digital Mission. It could provide model consent and vendor agreements with affordable cybersecurity support, and healthcare-specific implementation standards.

User data is routinely commoditised today, and passing a law assuming compliance and waiting for complaints or litigation will not suffice. As the DPDP Act comes into effect, the government must finance, build, and sustain an ecosystem that allows every health worker to comply and patients to be able to better access care.

(Dr. C. Aravinda is an academic and public health physician. Views expressed here are personal.
aravindaaiimsjr10@hotmail.com)

महत्वपूर्ण तथ्य

- डेटा शील्ड (सुरक्षा कवच) बनाने से पहले भारत को अपने स्वास्थ्य कर्मियों (Clinical Staff) को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

मुख्य बातें (Key Points):

- **DPDP अधिनियम और स्वास्थ्य क्षेत्र:** भारत के 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2023' के तहत डिजिटल स्वास्थ्य डेटा की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। इसके नियम 13 नवंबर 2025 को अधिसूचित किए गए थे, और इसके प्रावधान चरणों में लागू हो रहे हैं।
- **अस्पतालों के सामने चुनौतियाँ:** बैंकों या अन्य क्षेत्रों के विपरीत, अस्पतालों में मरीजों के स्वास्थ्य से जुड़ा संवेदनशील डेटा लगातार बनता और साझा होता रहता है। ऐसे में अस्पतालों के लिए सामान्य डेटा सुरक्षा कानूनों का पालन करना बेहद कठिन और जटिल है।
- **प्रशिक्षण और अनुपालन की कमी:** केवल कानून बना देना या भारी जुर्माना (₹250 करोड़ तक) तय कर देना पर्याप्त नहीं है। छोटे अस्पतालों, 诊क्विंस (Clinics) और स्वास्थ्य कर्मियों के पास डेटा सुरक्षा और अनुपालन (Compliance) के लिए आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण और एकसमान पाठ्यक्रम का अभाव है।
- **सरकार की भूमिका:** केवल कानून लागू करने के बजाय, सरकार को 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' के माध्यम से साझा बुनियादी ढांचा, किफायती साइबर सुरक्षा और मानक मॉडल उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि हर स्वास्थ्यकर्मी आसानी से नियमों का पालन कर सके।

महत्वपूर्ण तथ्य

WHAT IS IT?

Molecular machines

Vasudevan Mukunth

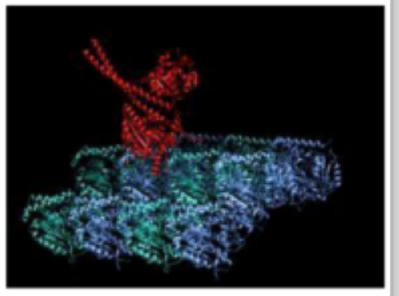
A molecular machine is a combination of molecules that converts energy into motion, to perform specific tasks. These are sophisticated systems — and nature makes abundant use of them.

A famous example is the protein kinesin, which transports minerals inside our body's cells by moving on microscopic tracks; another example is the protein myosin, which helps muscles contract.

Scientists have also been building artificial molecular machines since the 1980s. Specifically, in 1983, the French chemist Jean-Pierre Sauvage and his team reported a way to connect two ring-shaped molecules the same way an axle connects the wheels of a car.

Eight years on, the British-American chemist Fraser Stoddart & co. built a molecular structure where a molecular ring could move along an axle. Together with the Dutch chemist Ben Feringa, who led a team that built a molecular motor that could be driven by light, Sauvage and Stoddart won the chemistry Nobel Prize in 2026 for their work.

Fun though they sound, molecular machines are also quite finicky. At the scale of a molecule, random heat constantly jostles the structures, rendering their movements unpredictable. A molecule may also rotate or change its own position



The protein kinesin (red) attaches to and moves along microtubules (blue-green). KADEN.RAWSON, MARISAASADIAN, STEVENGPARKIN (CC BY-SA)

without moving anything else, presenting another challenge that comes in the way of coordinating multiple molecules.

But there have been advances apace. On October 22, for example, researchers reported in *Nature* that they had built a corkscrew-shaped molecule that, when suspended two electrodes, could cycle through a series of states when the current flowed one way and in the reverse direction when the current flowed the other way.

For feedback and suggestions for 'Science', please write to **science@thehindu.co.in** with the subject 'Daily page'

YouTube Homework

- Bio - Markers

महत्वपूर्ण तथ्य

- **मॉलिक्यूलर मशीनें (Molecular Machines)** या **आणविक मशीनें** ऐसे अत्यंत सूक्ष्म (नैनो-मीटर के आकार के) अणु होते हैं जो किसी बाहरी ऊर्जा (जैसे रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश या बिजली) को प्राप्त करके यांत्रिक गति (Mechanical Movement) या कार्य में बदलते हैं।
- सरल शब्दों में कहें तो, यह इंसानों द्वारा बनाई जाने वाली बड़ी मशीनों (जैसे कार या इंजन) का नैनो-स्केल (अत्यंत सूक्ष्म) रूप है, जो जीवित कोशिकाओं के अंदर या प्रयोगशाला में अणुओं के स्तर पर काम करता है।

मुख्य बिंदु (Key Points):

- **प्रकृति में उपस्थिति:** प्रकृति में आणविक मशीनें पहले से मौजूद होती हैं। उदाहरण के लिए, हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद **ATP सिंथेस** (जो ऊर्जा बनाता है) और **मायोसिन** (जो मांसपेशियों को सिकोड़ने में मदद करता है) प्राकृतिक आणविक मशीनें हैं।
- **कृत्रिम रूप (Artificial):** वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में भी ऐसी कृत्रिम मशीनें बनाई हैं। इसके लिए वर्ष 2016 का रसायन विज्ञान का **नोबेल पुरस्कार** जीन-पियरे सावेज, सर जे. फ्रेजर स्टोडार्ट और बर्नार्ड फेरिंगा को दिया गया था। उन्होंने दुनिया की सबसे छोटी मशीनें (रोटैक्सैन और कैटेनैन आधारित) बनाई थीं।
- **यह कैसे काम करती हैं:** ये मशीनें ऊर्जा मिलने पर अपनी आकृति (Shape) बदलती हैं, जिससे एक निश्चित गति पैदा होती है। ऊर्जा खत्म होने पर यह अपनी पुरानी स्थिति में लौट सकती हैं।

इसके उपयोग (Applications):

- **चिकित्सा (Medicine):** शरीर के अंदर सीधे किसी रोगग्रस्त कोशिका तक दवा (Drug Delivery) पहुँचाने के लिए इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकेगा।
- **नैनोटेक्नोलॉजी (Nanotechnology):** नैनो-रोबोटिक्स और स्मार्ट मटीरियल (सामग्री) बनाने में।
- **ऊर्जा संचयन:** सौर ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा को सीधे यांत्रिक कार्य में बदलने के लिए।

महत्वपूर्ण तथ्य

War, or no war, our policies remain unchanged, says Iran

We must accept the new realities, I'm already thinking about the post-war period, Araghchi says; his remarks come as U.S. President Trump indicated on Friday plans for a new military operation

Agence France-Presse
TEHRAN

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi said on Sunday that a potential resumption of war with Israel and the United States would not change his country's positions.

The remarks come amid mounting U.S. and Israeli threats of renewed attacks on Iran, as President Donald Trump said on Friday that Washington "may do another little Epic Fury," referring to the U.S.-Israeli campaign on Iran that began on February 28.

"Recently, there has been talk of a new war, but I am already thinking about the post-war period. Whether there is war or not, our policies remain the same," said Mr. Araghchiin Tehran.

"They have already done so twice and have seen the results. If they want to try again, they know they will achieve no different outcome from those of the past."

An April 8 ceasefire put an end to the most intense fighting, apart from sporadic exchanges of fire in and around the strategic Strait of Hormuz, a key route for global energy supplies.



Mural messaging: Motorcyclists drive past a billboard depicting a Persian legendary hero hitting U.S. aircraft carriers in Tehran. AP

Iran has claimed control over the strait since the outbreak of the war and has regularly targeted vessels that attempt crossing without its authorisation. In response, the U.S. has been maintaining a naval counter-blockade on Iranian ports.

In June, Iran agreed with the U.S. to a memorandum of understanding laying out a pathway to a permanent settlement of the conflict, only for the deal to later unravel as each side accused the other of violating it. Tehran has since called for a return to the accord to end the conflict.

"The current war has changed everything. We must accept that new realities are taking hold. Shipping routes through the Strait of Hormuz will no longer be the same, and the management of the strait will no longer be the same," Mr. Araghchi said.

"To achieve peace and stability, our region must move towards the complete absence of foreign forces."

Foreign Ministry spokesperson, Esmail Baghaei, said Tehran has not closed the window of diplomacy and messages are being passed to the U.S. via intermediaries.

State media said Mr. Baghaei spoke in an interview with a German broadcaster. He said the U.S. persist in unilateral demands and that Mr. Trump and U.S. officials repeatedly use the phrase "complete surrender," which Mr. Baghaei said no Iranian accepts.

Calls to cut gas usage

Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf on Sunday called for a campaign to cut gas usage by at least 10%, with officials anticipating shortages as winter approaches.

While a major producer, Iran has long suffered shortages of natural gas which have been exacerbated by war.

"To get through the approaching winter, a nationwide effort is essential ... to reduce gas consumption by at least 10%," Mr. Ghalibaf said.

(With inputs from AP)

महत्वपूर्ण तथ्य

Houthis target Riyadh airport hours after flights resume

Agence France-Presse
RIYADH

The Houthi militia in Yemen on Sunday launched wide-ranging strikes across swathes of southern Saudi Arabia even as the Iran-backed group said the kingdom struck Yemen dozens of times over the previous 24 hours.

The attacks targeted Riyadh's international airport hours after its partial reopening, as well as an airbase and naval base.

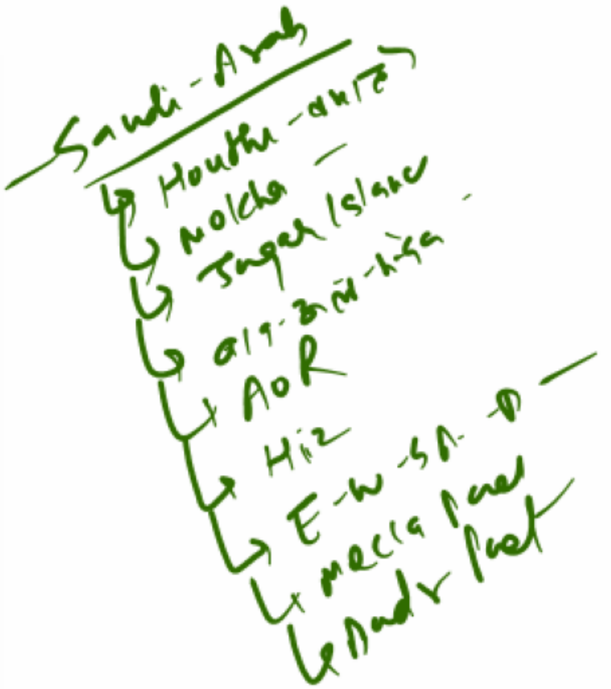
"The Yemeni armed forces conducted three military operations with dozens of ballistic missiles," Houthi military spokesperson Yahya Saree said on X, adding that the strike on the airport "achieved its target".

He added that they targeted King Khalid air base in Khamis Mushait and a naval base in Jazan.

The Saudi Arabia-led coalition fighting the Houthis earlier said at least 10 ballistic missiles were intercepted during.

The Houthi spokesperson warned that Riyadh airport was still "unsafe" and a "military target". He said Saudi Arabia launched 56 airstrikes and missiles targeting civilian infrastructures in Yemen over the previous 24 hours.

The King Khalid International Airport's website showed several domestic and international flights scheduled on Sunday, including arrivals from Dubai, Paris and Cairo, after being closed for two weeks. Tracking website Flightradar24 showed a small number of flights had departed, though the vast majority were cancelled.



महत्वपूर्ण तथ्य

Theoretical physicist Ashoke Sen wins Oskar Klein Medal

Vasudevan Mukunth

Theoretical physicist Ashoke Sen has been awarded the 2026 Oskar Klein Medal, becoming the first Indian laureate to receive the honour, awarded by Stockholm University and the Nobel Committee for Physics of the Royal Swedish Academy of Sciences.

The Medal recognises significant contributions to theoretical physics. Dr. Sen is the ICTS-Infosys Madhava Chair Professor at the International Centre for Theoretical Sciences (ICTS), Bengaluru. He also delivered the memorial lecture accompanying the Medal in Stockholm on October 22, titled "Gravity from Strings and Strings from Gravity".

In his career, Dr. Sen has focused on string theory, which is the name of an attempt by physicists to describe matter and nature's fundamental forces, including gravity, within a single framework called quantum gravity. Currently, they are split across two frameworks, quantum physics and relativity. String theory offers ways to reconcile them, but while it is mathematically a highly evolved theory, it has been unable to make predictions that can be confirmed with experiments using today's technologies.



Ashoke Sen is the first Indian to win this award. R. RAVINDRAN

In the 1980s, Dr. Sen helped establish how the equations describing hypothetical strings moving through space could relate to the equations that describe the physical fields that surround it. In the 1990s, he helped show that two apparently different ways to describe physical forces were really equivalent, an idea called S-duality.

Sen conjectures

He also proposed three related ideas, together called the Sen conjectures, in 1999 that gave physicists new ways to understand the behaviour of the strings of string theory. Dr. Sen graduated from Presidency College in Kolkata before going to IIT-Kanpur and thereon to earning his Ph.D. from Stony Brook University, New York, in 1982. After working at institutions including the Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) in Mumbai and the Harish-Chandra Research Institute (HRI) in Prayagraj, he moved to ICTS in 2021.

For his work, he has won the S.S. Bhatnagar Prize (1994), the Infosys Prize (2009), the Breakthrough Prize in Fundamental Physics (2012), and the Dirac Medal (2014).

He also received the Padma Shri in 2001 and the Padma Bhushan in 2013.

The impact of Dr. Sen's contributions has exceeded their own ambit. In one 2014 interview, U.S. theoretical physicist Edward Witten – widely considered to be the greatest living mathematical physicist – called one of Dr. Sen's papers "short but brilliant" and that it "convinced me that the duality had to be right". Dr. Witten also said Dr. Sen's findings had inspired work that paved the way for more breakthroughs in understanding how subatomic particles interact with each other.

He has also done important work on black holes. Physicists had long known that these enigmatic cosmic beasts had entropy but could not explain its origins in their physical theories. Dr. Sen developed mathematical methods to make sense of a black hole's microscopic states in a way that could account for its observable, macroscopic characteristics.

Together, many physicists agree, his contributions have considerably advanced the theories physicists use to understand quantum gravity.

The Oskar Klein Medal and the accompanying Memorial Lectures was launched in 1988 to honour the Swedish physicist Oskar Klein (1894-1977). In 1926, Klein, building on the work of German mathematician Theodor Kaluza, explored whether electromagnetism and gravity could be described in a common framework by introducing an extra dimension of space. The result, known as Kaluza-Klein theory, exerted a significant influence on later attempts by physicists – including string theory – to unify these forces.

India in particular has an influential community of string theorists, especially at TIFR Mumbai, ICTS Bengaluru, HRI Prayagraj, and the Indian Institute of Science Education Research in Pune. Aside from Dr. Sen, the community's notable members include Nabamita Banerjee, Shiraz Minwalla, Sunil Mukhi, P. Ramadevi, and Spenta Wadia.

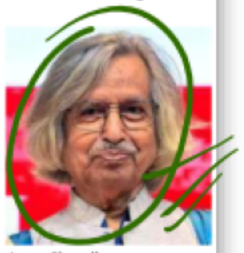
YouTube Homework

Nobel Prize

महत्वपूर्ण तथ्य

Jogen Chowdhury, eminent painter and ex-MP, passes away

Shiv Sahay Singh
KOLKATA


Jogen Chowdhury

Eminent painter and former Rajya Sabha member Jogen Chowdhury died at a private hospital in Kolkata on Sunday morning. He was 87. He was admitted to the hospital on October 16 after his health deteriorated and was put on ventilator support on Saturday.

Born in Faridpur, now in Bangladesh, on February 15, 1939, Mr. Chowdhury developed an interest in drawing at a young age. During the Partition, he moved to Kolkata with his family. He studied at the Government College of Art and Craft in Kolkata before pursuing further studies at École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris. In the early years, he worked in an expressionist style of figuration. His paintings used human forms and were often a satire on politics and society.

Mr. Chowdhury joined the faculty at Visva-Bharati University in Santiniketan in 1987 after serving as Keeper of Art at the Rashtrapati Bhavan. Over the past few years, he had been associated with the design of art installations during Durga Puja.

The Delhi Art Gallery, in a description of his work on its website, said Mr. Chowdhury interpreted the "human form through the X-ray vision of his creativity: attenuated, exaggerated, fragmented, reconfigured, and rephrased".

West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari condoled the artist's death, saying his contributions had brought international acclaim to West Bengal and his passing left an irreparable void in the State's intellectual and artistic soul.

Former Chief Minister Mamata Banerjee had nominated Mr. Chowdhury to the Rajya Sabha on Trinamool Congress ticket. He served in the Upper House from 2014 to 2020. In 2012, the Trinamool Congress government conferred on him the Banga Bibhushan, one of the State's highest civilian honours. Painter Samir Aich described Mr. Chowdhury as a stalwart of contemporary art who always stood by fellow artists.

महत्वपूर्ण तथ्य

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

एनआईएफटीईएम-के ने भारत के पहले 'एआई × फूड टेक हैकाथॉन', 'हैक द फोर्क' का आयोजन किया

प्रविष्टि तिथि: 25 OCT 2026 7:41PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली (एनआईएफटीईएम-के) ने 'हैक द फोर्क' का आयोजन किया। यह भारत का पहला 'एआई × फूड टेक हैकाथॉन' था। इसका मुख्य उद्देश्य वैकल्पिक प्रोटीन उद्योग की वास्तविक चुनौतियों को हल करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का सदुपयोग करना था। 24 घंटे तक चले इस हैकाथॉन का उद्घाटन 24 अक्टूबर को 'हैक द फोर्क' की निदेशक सश्री ऐलिस पीजी ने किया था। 25 अक्टूबर को संपन्न हुए इस कार्यक्रम में, भाग लेने वाली टीमों ने विशेषज्ञों की जूरी के सामने अपने नवीन समाधान प्रस्तुत किए।



महत्वपूर्ण तथ्य

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

शिल्प समागम मेला 2026-गुवाहाटी

गुवाहाटी के खानापारा के फार्म गेट में चल रहे मेले में हज़ारों आगंतुकों ने भारत की पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद की समृद्ध और विविध विरासत देखी

प्रविष्टि तिथि: 25 OCT 2026 7:03PM by PIB Delhi

गुवाहाटी में शिल्प समागम मेले (एसएसएम) से स्थानीय लोगों में उत्साह भर रहा है और हज़ारों दर्शकों ने भारत की पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की समृद्ध और अलग-अलग तरह की विरासत देखी है।

21 अक्टूबर को शुरू हुआ यह मेला असम की राजधानी गुवाहाटी में लगातार पांचवे दिन आस पास के इलाकों से लोगों को अपनी ओर खींच रहा है।

इसके अलावा, दुकानदार अच्छी आय कमा रहे हैं क्योंकि मेले में आने वाले दर्शकों को अलग-अलग तरह के विशिष्ट और रंगीन हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद खरीद रहे हैं। मेला यहां आए ग्राहकों को सीधे उत्पाद खरीदने का मौका देता है जिससे महिलाओं और दूसरे कारीगरों को अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलती है।



महत्वपूर्ण तथ्य

लोकसभा सचिवालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

12वां ब्रिक्स संसदीय मंच कल संसद भवन परिसर में आयोजित होगा

ब्रिक्स मंच से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ने रूसी संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठक की

भारतीय एवं रूसी संसदीय प्रतिनिधिमंडलों ने वैश्विक मंचों पर सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद से निपटने हेतु सामूहिक प्रयासों पर चर्चा की

लोकसभा अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए रूस के समर्थन की सराहना की

लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के नियमित आदान-प्रदान और युवा एवं महिला सांसदों के बीच संवाद को बढ़ावा देने पर बल दिया

2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन-केंद्रित दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित होगी: लोकसभा अध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्ष ने क्यूबा, मिस्र और बेलारूस के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात की

प्रविष्टि तिथि: 25 OCT 2026 4:20PM by PIB Delhi

12वां ब्रिक्स संसदीय मंच (12th BRICS Parliamentary Forum) का आयोजन 26 और 27 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली, भारत में होना तय हुआ है।

इस आयोजन से जुड़ी मुख्य जानकारियां निम्नलिखित हैं:

- **तिथि:** यह दो दिवसीय सम्मेलन **26 और 27 अक्टूबर 2026** को आयोजित किया जा रहा है।
- **स्थान:** इसका आयोजन नई दिल्ली में संसद भवन परिसर के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष (**संविधान सदन**) में किया जा रहा है।
- **मुख्य थीम:** इस बार इस मंच का मुख्य विषय **"जन-केंद्रित विकास हेतु संसदों का सुदृढ़ीकरण"** (Fostering Parliaments for People-Centric Development) रखा गया है। Press Information ... +3

महत्वपूर्ण तथ्य

प्रधानमंत्री कार्यालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में आरबीआई के नवनिर्मित डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया

एक अधिक सुरक्षित वित्तीय प्रणाली की ओर एक बड़ा कदम; भुवनेश्वर में आरबीआई की नई सुविधाएं डिजिटल बुनियादी ढांचे और साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करेंगी: प्रधानमंत्री

महाप्रभु के आशीर्वाद से, आज भुवनेश्वर नए भारत को एक नया संस्थान दे रहा है; भुवनेश्वर में आरबीआई के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान दोनों का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अवसर है; यह ओडिशा के लोगों और देश के लिए बहुत फायदेमंद होगा: प्रधानमंत्री

हम जन-हितैषी, सक्रिय और सुशासन के मॉडल से प्रेरित हैं; हमारे लिए विकास का अर्थ भारत की न्यायसंगत प्रगति है, जहाँ अवसर हमारे गाँवों और छोटे शहरों तक एक समान पहुँचें: प्रधानमंत्री

आज डिजिटल बैंकिंग ने हर भारतीय को 24 घंटे की बैंकिंग सेवाओं से जोड़ दिया है: प्रधानमंत्री

आज जिनके पास बैंक को गारंटी के रूप में देने के लिए कुछ भी नहीं है, वे भी किफायती और सुलभ ऋण प्राप्त करके अपना काम शुरू करने में सक्षम हैं; छोटे उद्यमियों से लेकर पारंपरिक कारीगरों तक, रेहड़ी-पटरी वालों से लेकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक, पहली बार उन्हें औपचारिक बैंकिंग का लाभ मिला है: प्रधानमंत्री

महत्वपूर्ण तथ्य

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

‘विकसित भारत 2047’ की दिशा में शहरी प्रशासन, योजना और सेवाओं की आपूर्ति को मजबूत करने संबंधी व्यावहारिक सुझावों के साथ ‘राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2026’ संपन्न

“इस सम्मेलन का उद्देश्य हमारे शहरों के सामने आने वाली भविष्य की चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना है”: श्री मनोहर लाल, माननीय केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री

सात तकनीकी सत्रों में समावेशी, सुदृढ़ और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार शहरों के निर्माण हेतु प्रमुख सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई

प्रविष्टि तिथि: 25 OCT 2026 3:42PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन (National Urban Conclave) का आयोजन मुख्य रूप से भारत सरकार के **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs - MoHUA)** द्वारा किया जाता है। Press Infor...

इस सम्मेलन से जुड़ी प्रमुख जानकारियां नीचे दी गई हैं:

- **आयोजनकर्ता (Who Organizes):** इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों और **राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (NIUA)** (ज्ञान भागीदार/Knowledge Partner) के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इसके अलावा हुडको (HUDCO) और एनबीसीसी (NBCC) जैसी संस्थाएं इसकी मुख्य प्रायोजक होती हैं। Press Information Bur...
- **कब होता है (When It Happens):** यह एक **वार्षिक (Annual)** मंच या सम्मेलन है, जिसका आयोजन अमूमन हर साल अक्टूबर या नवंबर महीने के आस-पास किया जाता है। उदाहरण के लिए:
  - **2025 का सम्मेलन:** इसका आयोजन 8-9 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के 'यशोभूमि' में किया गया था।
  - **2026 का सम्मेलन:** इसका दूसरा संस्करण हाल ही में 24-25 अक्टूबर 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। Press Information ... +2

महत्वपूर्ण तथ्य

Home Assignment

- National Girl Child Day
- Make in india

प्रश्न:

- **हाल ही में चर्चा में रहा "AL-Hudaydah" निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, जिसे एक नए आर्थिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है?**

A. सऊदी अरब
B. यमन
C. संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
D. ओमान

Thanks For Watching

Learn
Share
Grow
Together ♡

Better
Students
Brighter
Tomorrow

Follow us for more Updates

@RRESULTMITRAOFFICIAL

Join our Telegram

@SUNILVERMA_THEIASMENTOR

Follow on Instagram

Subscribe Now

Stay Connected



